## कल्पतरू एक्सप्रेस में दो जुलाई 2014 से 7 अक्टूबर 2014 के बीच कुमार मुकुल के लिखे गए 49 संपादकीय

**विकास और बर्बरता 2-7-2014**

क्कीसवीं सदी तकनीक और विकास की सदी मानी जा रही है, पर जिस तरह से बर्बरता और हिंसा के प्रति लोगों का रुझन इस सदी में दिख रहा है वह विकास के इस पूरे माहौल को सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। आतंक और भय पूरी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ता जा रहा है। आम आदमी की तो इस सारी उठा-पटक में कोई बकत नहीं दिखती है, खास आदमी भी अपना संयम खोता हुआ भाषा और व्यवहार में बर्बर होता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के 'रेप करवा दूंगा' वाला बयान स्त्री के प्रति उनकी मानसिकता को ही जाहिर कर रहा है। अब उनके माफी मांगने से उनकी मानसिकता खत्म नहीं हो जाती। कुछ महीने पहले रूस में यूक्रेन पर प्रतिबंधों को लेकर एक क्रेमलिन समर्थक रूस की संसद के डिप्टी स्पीकर व्लादिमिर जिरोनस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां उपस्थित छह महीने की गर्भवती एक महिला रिपोर्टर स्टेला दुबोवित्सकाया के सवाल पर आगबबूला होते हुए अपने दो सहयोगियों से कहा था कि इसका रेप करो। इससे डरकर महिला पत्रकार बेहोश हो गयी थी। बाद में जिरोनस्की ने रूस के टेलीविजन पर एक लाइव इंटरव्यू में इस हरकत के लिये माफी मांगी थी। पॉल की पत्नी भी तापस के इस बयान के लिए माफी मांग रही हैं, पर यहां सवाल उठता है कि क्या हमारे माननीयों के ऐसे व्यवहार के बाद उसका माफी मांग लेना पर्याप्त है? आज जिस तरह पढ़ी-लिखी चेतन स्त्री पारंपरिक पुरुष सत्ता का लगातार प्रतिकार करती हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, उससे हतप्रभ सामंती मिजाज का पुरुष हमलावर होता जा रहा है। नतीजतन स्त्री के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और घमंडी व मूर्ख पुरुष खुद को विकसित और सुसंस्कृत करने की बजाय अभद्र भाषा का व्यवहार कर अपनी कुंठा को शांत करने की कोशिश करते हैं।

विरोधी दलों और महिला संगठनों की ओर से तापस को बर्खास्त और गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर से तापस पाल के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की है। इस बीच, उनकी पत्नी ने सफाई देते हुए माफी मांगी है। तृणमूल ने उनके बयान से पल्ला झड़ते हुए इस पर 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। सीपीएम तापस के बयान के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की सोच रही है और महिला आयोग का मानना है कि तापस को गिरफ्तार कर बर्खास्त कर देना चाहिए। आयोग ने यह सवाल भी उठाया है कि अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने भी सांसद के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है। तापस के बर्बर वक्तव्य का वीडियो भी सामने आया है। आज तकनीक के विकास से यह तो हुआ है कि लोगों का बर्बर व्यवहार कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है और वह लोगों को उसके खिलाफ खड़े होने का मुकम्मल आधार प्रदान करता है। पर तकनीक से होड़ लेती बर्बरता हमारे विकास पर एक प्रश्न चिह्न् ही है।

**शर्म या गर्व 22-9-2014**

ह कैसी विडंबना है कि जिस समय उत्तर प्रदेश के बल्देव के आंगई ग्राम की बेटी और मथुरा की बहू अंतरराष्ट्रीय शूटर श्वेता 17 वें एशियाई खेलों में

भारत के लिए पदक जीतकर एक नई शुरुआत कर रही थीं, उसी समय उत्तर प्रदेश के ही औरैया में छेड़खानी का विरोध करने के कारण एक युवती को जिंदा जलाकर मारा जा रहा था। अछल्दा थाना के गांव मदा का पूर्वा की इस युवती का क्या यही दोष था कि उसने शोहदों द्वारा छेड़खानी का विरोध किया था? एक माह पूर्व छेड़खानी की पुलिस में शिकायत का ऐसा खौफनाक परिणाम उसे भुगतना पड़ा। फिर यह कोई अपनी तरह की अकेली घटना नहीं है। ज्यादा समय नहीं बीता जब कानपुर देहात में एक परिवार को बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया था और दबंगों ने पूरे परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया था। उत्तर प्रदेश में विवाहिताओं के जिंदा जला दिए जाने की खबरें यहां के अखबारों में रोजाना ही रहती हैं, जिनमें अधिकांशत: दहेज के लिए जलाई जाती हैं। लव जिहाद की नकली खबरें गढ़ने वालों के लिए पता नहीं यह सब मुद्दा क्यों नहीं बनता? साथ ही महिला अपराधों में अव्वल आ रही उत्तर प्रदेश सरकार की सेहत पर इसका कोई असर पड़ता दिखता है। पिछले महीने ही संसद में नियम 193 के तहत देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर से संबंधित विषय पर समाजवादी पार्टी की सदस्य और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव महिला भाजपा सांसद के सवाल पर असहज हो गई थीं, तब उनके देवर धर्मेन्द्र यादव उनके बचाव में कुछ बोलने को खड़े हुए थे और पीठासीन सभापति ने कहा था कि उनको (डिंपल) वकील नहीं चाहिए, आप बैठ जाइए।

**<u>स्त्री अस्मिता का सवाल 3-5-2014</u>**

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के स्वीकार के बाद कि वे टीवी एंकर अमृता राय के साथ शादी करने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया में इस रिश्ते को लेकर जिस किस्म का घमासान मचा है वह सोशल मीडिया पर काबिज लोगों में तेजी से पैठ बना रही कुंठा को जाहिर कर रहा है। वस्तुस्थिति को देखने-समझने और उस संदर्भ में कोई बात कहने की जगह वे अपने-अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले जशोदाबेन प्रकरण पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस आदि ने जिस तरह से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को सवालों के घेरे में ला दिया था सहज ही उन्हें भी हमले को एक जमीन मिल गयी है और अब वे चरित्र के नाम अगर चरित्रहनन करने को नैतिकता बता रहे हैं तो चुनावी परिपेक्ष्य में इस सारी उछलकूद का लक्ष्य अपनी भोली जनता को उल्लू बनाने से ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव बाद इन तमाम नेताओं की गलबहिंया हमेशा की तरह जारी हो जाएगी और आजू-बाजू बैठकर बीच-बीच में उठ रहे मसलों की जुगाली करते हुए वे अगला पांच साल गुजार देंगे। इस मुद्दे पर भाजपा ने नैतिकता और वैधता का सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व से संज्ञान लेने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि तलाक नहीं होने के कारण गुप्त विवाह संभव नहीं है। ऐसे में आपराधिक मामला भी बनता है लेकिन यह पति के ऊपर निर्भर करता है। पर इस मामले में भाजपा और अन्य तमाम विरोधी इस पति नामक जीव को इस तरह दरकिनार कर रहे हैं जैसे इसके बीच में आते ही उनकी नैतिकता का बाजा बज जाने वाला हो।

सोशल मीडिया में मची हलचल पर अमृता राय के पति प्रोफेसर आनंद प्रधान ने नाराजगी जताते स्पष्ट कहा है कि 'हमारे बीच संबंध बहुत पहले से खत्म हो चुके हैं।

अलग होने के बाद अमृता अपने बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं।' जो लोग स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को सामंती सोच से बाहर आकर देखने को तैयार नहीं उनसे श्री प्रधान इससे ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं करते। इस मामले में जहां दिग्विजय सिंह के बेटे कांग्रेस महासचिव और विधायक जयवर्धन सिंह ने पिता के मामले को पूरी तरह से उनका निजी मामला बताते हुए उसका समर्थन किया है वहीं दिग्विजय के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह ने नाराजगी जताते कहा है कि 'मैं दिग्विजय सिंह से नाराज हूं क्योंकि उन्होंने उनके छोटे भाई से मेरी शादी का विरोध किया था। इसकी वजहें उन्होंने ये बताई थीं कि मैं लक्ष्मण सिंह से 13 साल छोटी हूं और राजपूत भी नहीं हूं।' यहां रूबीना की खुन्नस को जायज माना जा सकता है। उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है। रूबीना ने भी लक्ष्मण सिंह की पहली पत्नी के कैंसर से मरने पर ही लक्ष्मण सिंह से संबंध बनाया था। अब उनकी ही तरह अमृता राय का दिग्गी राजा से प्रेम और विवाह करने का अधिकार कम नहीं हो जाता।

**<u>संसद में फ्लाप सचिन 9-8-2014</u>**

केट में शतकों का पहाड़ लगाने वाले 2012 में राज्यसभा के लिए नामित भारत र} सचिन तेंदुलकर का एक सांसद के रूप में रिकॉर्ड भी बहस का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि मास्टर ब्लास्टर ने इस साल संसद में अपना खाता तक नहीं खोला है। 2013 में भी उन्होंने मात्र तीन दिन सत्र में भाग लिया था। इतना ही नहीं सचिन ने अब तक किसी भी संसदीय बहस में हिस्सा नहीं लिया है। यूं तो ऐसे निष्क्रिय सांसदों की जमात बड़ी है जो संसद नहीं जाते, लेकिन सचिन ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। कहां तो सचिन से उम्मीद थी कि वह संसद में जाकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएंगे, पर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आज तक संसद का रुख नहीं किया। राज्यसभा में शुक्रवार को माकपा के सदस्य पी राजीव ने सचिन व रेखा जैसी मनोनीत हस्तियों की सदन में अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। मास्टर ब्लास्टर ने सदन की पिछली 40 बैठकों में भाग नहीं लिया है। नियम के तहत

60 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

इस संदर्भ में सचिन की शख्सियत का समग्र विषण करने पर निराशा हाथ लगती है। मैदान से बाहर शायद ही उन्होंने कभी कोई ऐसा काम करके दिखाया हो जिससे उनके प्रति सम्मान पैदा हो। पाकिस्तान के नामी क्रिकेटरों इमरान खान और इंजमाम-उल-हक ने अपने यहां जनहित में अस्पतालों की स्थापना की है। पर, सैकड़ों करोड़ कमाकर भी सचिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या सचिन जैसे नायक सिर्फ ब्रांड एम्बेसडरी के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या समाज को लेकर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर इस समाज ने ही उन्हें 'भगवान' माना है। भारत में आमिर खान, विवेक ओबराय जैसे सेलिब्रिटी भी हैं जो जनहित में काम कर अपनी लोकप्रियता को एक अर्थ देने की कोशिश करते हैं। इसके उलट सचिन भेंट में मिली फेरारी पर लगने वाली ड्यूटी माफ कराने के लिए सरकार के मुंहताज दिखते हैं। आगे जब सचिन ने यह कार बेच दी, तब महात्मा गांधी के परपौत्र ने इस पर कठोर टिप्पणी की थी। क्रिकेट और विज्ञापनों से करोड़ों कमाने वाले सचिन पैसे के लिए बाजार में अलिखित तौर पर मान्य र्मयादा तक का ध्यान नहीं रखते और एक की ब्रांड एम्बेसडरी खत्म होने पर तुरंत उसकी राइवल कंपनी का दामन थाम लेते हैं। सदन के बाहर राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने सचिन की गैरहाजिरी पर तंज कसते हुए कहा कि संसद की सदस्यता कोई ट्रॉफी नहीं कि लेकर चले गए। यूं अख्तर की इस बात पर सोशल मीडिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष सवाल उठाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोट नहीं डालने वाला शख्स ऐसी बात न करे। सचिन ने ट्वीट कर सफाई भी दी है कि वे अपने भाई के ऑपरेशन में व्यस्त थे। पर, जब सवाल देश और संसद का हो तो बचाव में ऐसे तर्क सचिन जैसी शख्सियत का मजाक ही बनाते हैं। यूं संसद में ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले सचिन अकेले नहीं हैं, अलबत्ता गोविंदा, धर्मेंद्र , विजय माल्या, नवजोत सिंह सिद्धू आदि उनके आगे-पीछे ही हैं।

**<u>अपराध और किशोर 8-8-2014</u>**

द्रीय केबिनेट द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव पर मुहर लगा देने के बाद किशोर अपराध पर नए कदमों के सहारे कानून को संशोधित करने की पहल मजबूत हुई है। हालांकि, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 साल के बीच के किशोरों पर मुकदमा चलाने के फैसले का हक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ही होगा, पर मामला और आरोपी को देखकर बोर्ड के पास यह तय करने का हक होगा कि मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा या फिर सामान्य अदालत में। संयुक्त राष्ट्र का बाल कानून कहलाने वाला बीजिंग रूल्स भी कहता है कि आपराधिक जिम्मेदारी के मामले में उम्र का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर करना होगा कि उसकी मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता कैसी है? इसलिए सीधे तौर पर नाबालिग की उम्र घटाने के बजाय गंभीर अपराध में शामिल आदतन अपराधी हो चुके 16 से 18 साल के किशोरों को दंडित करने की व्यवस्था जरूर हो रही है। किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) कानून-2000 के मुताबिक 18 साल की उम्र तक के अपराधियों को किशोर माना जाता है। ऐसे अपराधियों को किसी भी मामले में दोषी होने पर तीन साल तक के लिए बाल सुधार गृह भेजा जाता है। पर, निर्भया कांड के बाद से गंभीर अपराध में शामिल नाबालिगों को बालिग मानकर सजा देने की मांग जोर पकड़ती गई थी। सरकार से नाबालिग आरोपी की उम्र 18 से घटाकर 16 करने की भी मांग की गई थी। दिल्ली में दिनदहाड़े बर्बर हत्याओं को अंजाम देने वाले ज्यादातर नाबालिग बताए जा रहे हैं। लिहाजा यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसे निर्मम अपराधियों को नाबालिग शब्द की आड़ में अपराध करते रहने की छूट दी जानी चाहिए?

अलग-अलग देशों में अपराध के हिसाब से किशोरों को सजा के अलग-अलग प्रावधान हैं। अमेरिका में संगीन अपराध में ज्यादातर राज्यों में उम्र सीमा 13-15 साल की है। संगीन अपराध पर केस आम अदालत में ट्रांसफर किया जाता है। इंडियाना, साउथ डकोटा, वरमॉन्ट में तो संगीन अपराध पर नाबालिग उम्र सीमा 10 साल तय की गई है। अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के संगीन अपराधियों को भी उम्र कैद का प्रावधान है। ब्रिटेन में 18 साल से कम उम्र के अपराधियों के लिए अलग अदालत है। वहां भी हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में केस आम अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फ्रांस में नाबालिग की उम्र 16 साल है। सऊदी अरब में हाल ही में बैंक लूटने पर 7 नाबालिगों को मौत की सजा दी गई।

यूं किशोरों से जुड़े कानून में संशोधन करने के केन्द्र के प्रस्ताव से बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहमत नहीं है। पहले भी आयोग की अध्यक्ष कुशल सिंह ने कहा था कि यदि बच्चा गंभीर अपराध करता है तो उसके लिए विपरीत सामाजिक परिस्थितियां दोषी हैं, जिनका वह शिकार बनता है। ऐसे हालात में दंडात्मक कार्रवाई समस्या का दीर्घकालिक हल नहीं है, बल्कि बच्चों के उचित संरक्षण और देखभाल समेत सुधारात्मक कदम से उनको जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद की जानी चाहिए ताकि समाज में बाल-अपराध की दर कम हो। यह भी देखा जाए कि बाल अपराधियों को पुलिस आसानी से मारपीट कर बातें मनवा लेती है। इस लिहाज से मामले को ना केवल कानूनी तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके सामाजिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

**<u>संघ, माओ और पूंजीवाद 5-8-2014</u>**

भी माओ का उदाहरण देकर और अब पूंजीवाद की बढ़त को देश के लिए खतरनाक बताकर भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक आधार प्रदान करने वाला

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या समय के बदलते रुख के साथ क्रांतिकारी करवट लेने की कोशिश कर रहा है? मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित चिंतन बैठक के आखिरी दिन आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने बढ़ते पूंजीवाद को देश के लिए घातक बताते हुए कहा है कि स्वावलंबन और स्वाभिमान की बुनियाद पर देश से गरीबी समाप्त हो सकती है। इसी साल 23 फरवरी को भोपाल में ही र्शी भागवत ने संघ की चार दिवसीय क्षेत्रीय बैठक के समापन उद्बोधन में समता एवं शारीरिक कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करते हुए चीन के नेता माओ को उद्धृत करते हुए कहा था कि माओ ने समाज को शारीरिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही क्रान्ति के लिये तैयार किया था। माओ के इस कथन से उन्होंने सहमति व्यक्त की कि सब बातें जड़ हैं, इसलिये शरीर ठीक करो तो सब ठीक हो जायेगा।

मोहन भागवत को एक ऐसे व्यावहारिक नेता के रूप में देखा जाता है, जो हिन्दुत्व के विचार को आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे ले जाने की बात करता है। अपने समय में आम जन से जुड़ने की इसे मजबूरी भी कहा जा सकता है। यह यूं ही नहीं था कि संघ की पहल पर आडवाणी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने वाले नरेन्द्र मोदी ने पिछले चुनावों में आम जन को संबोधित करने को जो भाषा अपनायी, उसमें बड़बोलेपन के साथ आम लोगों की भावनाओं को तोष देने की कोशिश भी लगातार दिखी। इसलिए चुनावों में मंदिर की जगह शौचालय तक की बात उठी और विकास मुद्दा बना और मोदी ने खुद को चाय बेचने वाला कहे जाने की व्याख्या को आमजन और गरीबों से जोड़ा, जिसका उन्हें फलाफल भी मिला। र्शी भागवत ने बदलते समय के साथ चलने पर बल देते हुए संगठन का आधार समृद्ध और प्राचीन भारतीय मूल्यों में दृढ़ बनाए रखने की कोशिश की है। उन्होंने इस प्रचलित धारणा के विपरीत कि संघ पुराने विचारों और मान्यताओं से चिपका रहता है, आधुनिकीकरण को स्वीकार करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि हिन्दू समाज में जातीय असमानताओं और अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होने की बात भी वे कहते रहे हैं। स्पष्ट है कि र्शी भागवत तेजी से बदलते इस समय में पारंपरिक आधारों की सीमाएं जानते हैं, इसलिए वे कह पाते हैं कि भारत तो अमीर देश है, पर भारतीय गरीब हैं और इसे दुरुस्त करने के लिए भारत की आर्थिक नीतियों में सुधार की जरूरत है। उनकी समझ में यह आ रहा है कि जिस गरीबी को हटाने को मोदी प्राथमिकता बता रहे हैं, उसे अकेले संघ और भाजपा के बूते नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए भागवत ने अन्य राजनीतिक दलों से भी गरीबी मिटाने के लिए पहल करने की अपील की है। जिस बाहरी खतरे का बिगुल चुनावों में भाजपा और उनके पक्षधर करते रहे, उसे भी भागवत ने नकारते हुए कहा है कि देश को बाहर से कम, अंदर से ज्यादा खतरा है। अब यह बदलाव कितना फायदेमंद सिद्ध होगा, यह वक्त ही बेहतर बताएगा।

**<u>पारस्परिक पीठ ठोकाई 4-10-2014</u>**

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन के समय चीनी सेना की चुमार में उपस्थिति से हुए मानमर्दन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की स्वप्रचारित सफलता से लहालोट भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की सफलता सताने लगी है। इसी संदर्भ में मोदी ने गांधी जयंती को स्वच्छता अभियान के बहाने जन संपर्क का माध्यम बनाया और फिर लगे हाथ रेडियो से भी जनता को संबोधित किया। पिछले उपचुनावों में लगातार कई राज्यों में भद्द पिटवाने के बाद भाजपा और आरएसएस आगामी चुनावों में जनता को प्रभावित करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने देना नहीं चाहते। इसी उत्साह में सरकार ने प्रधानमंत्री के रेडियो संबोधन के अलावा भागवत का संबोधन भी दूरदर्शन पर करवा डाला। संबोधन का अंदाज भी ऐसा जैसे कि वे सरकार की ओर से राष्ट्र की नीतियां तय कर रहे हों।

संघ के 89 वें स्थापना दिवस पर अपने विजयादशमी संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले चार महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े विषयों पर की गई पहलों के लिए जिस प्रकार मोदी सरकार की प्रशंसा की, उसे लेकर कांग्रेस तथा माकपा ने सरकारी प्रसारक का दुरुपयोग करने के लिए सरकार पर उचित ही निशाना साधा है। बीते दस सालों की संप्रग सरकार उससे पहले की वाजपेयी की भाजपा सरकारों के दौरान कभी भी आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर नहीं हुआ था। अब बचाव की मुद्रा में आईभाजपा ने कहा कि आरएसएस ने वास्तव में देशभक्ति के लिए योगदान दिया है और हमेशा ही सभी के लिए न्याय के दर्शन का अनुकरण किया है। इस तरह से सरकार और संघ एक-दूसरे की पीठ-ठोकाई में लग गए हैं। हालांकि, अपने संबोधनों में दोनों ने जनता से अपने आत्मविश्वास की मजबूती की बात की है, पर इसके भीतर उपचुनावों की हार के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के दशकों पुराने साथ के टूटने की पीड़ा को भी देखा जा सकता है। भागवत द्वारा लोगों से सरकार को थोड़ा और समय देने, ताकि वह अपनी नीतियों को तेजी और प्रभावी ढंग से लागू कर सके, के र्मम को उपरोक्त संदभरें में साफ-साफ समझा जा सकता है। लोकसभा चुनावों में जादुई व्यक्तित्व वाले नमो के टूटते जादू का अहसास भागवत को भी है। इसीलिए अब भागवत ने भी स्वीकारा है कि मोदी के पास बदलाव के लिए जादू की छड़ी नहीं है।

मोदी द्वारा मुसलमानों को देशभक्त पुकारे जाने के बाद भागवत ने भी मुस्लिम कट्टरपंथ के लिए पश्चिमी देशों के स्वार्थ को जिम्मेदार माना है। भागवत ने पश्चिम एशिया से तेल लेने से जुड़े पश्चिमी देशों के स्वार्थी हितों को वहां इस्लामिक स्टेट की आतंकी गतिविधियां बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराते कहा है कि पश्चिम एशिया में आतंक एवं कट्टरपंथ के नए चक्र आइएसआइएस के लिए पूरी तरह से पश्चिमी देशों का स्वार्थ जिम्मेदार है। भागवत ने कहा कि भारत दुनिया का बड़ा भाई है। पहले हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही बड़े भाई हुआ करते थे, पर मोदी के सत्ता में आने पर हम दुनिया के

बड़े भाई हो चुके हैं। पता नहीं भागवत के इस वक्तव्य पर खुद को सबका बड़ा भाई मानने वाला अमेरिका क्या सोचेगा? यह बात और है कि भागवत ने मोदी की अमेरिका यात्रा के भी गुण गाए हैं जिससे बात आई-गई होने की संभावनाएं हैं ही।

**शोहदों वाली भाषा 18-1-2014**

मारे राजनेता आज जिस तरह की सतही भाषा में एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, उसकी तुलना केवल सड़क छाप शोहदों की टोंटबाजी से की जा सकती है। आश्चर्यजनक है कि यह सब नये नवेले राजनीतिज्ञ नहीं कर रहे बल्कि जो पके पकाए हमारे राजनेता हैं वे ऐसे हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, अगर वह यहां चाय बांटना चाहते हैं, तो उन्हें जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। भाजपा के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी ने इसका जवाब अय्यर की शैली में ही देते हुए कहा कि चाय की दुकान कौन लगाएगा, यह चुनाव के बाद पता चलेगा।

अय्यर विदेश सेवा में रहे हैं और कभी उन्होंेने पत्रकारिता भी की थी। उन जैसे नेता से ऐसे अमर्यादित व्यवहार की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है? इस मुद्दे पर जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर सही और संतुलित भाषा में कहा कि मोदी में काफी नकारात्मक बाते हैं, पर उनका अत्यंत गरीब परिवार से आना सकारात्मक बात है। हम अपने बारे में ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। उनक मजाक उड़ाकर हम अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहां देखें तो अय्यर की सतही बातों का जो जवाब मुरली मनोहर जोशी ने दिया है वह भी उतना ही सतही है कि चाय कौन बेचेगा यह चुनाव के बाद पता चलेगा।

मतलब जोशी को भी चाय बेचने जैसी शब्दावली पर ऐतराज नहीं है। बस, इस क्रिया को वे अपने लिए नहीं अपने विपक्षी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं।

यहां देखें तो राहुल की शब्दावली अपेक्षाकृत शालीन साबित होती है। आम चुनाव के प्रचार प्रमुख की जिम्मेवारी संभालते हुए राहुल गांधी ने अपने संबोधन में विपक्षी दल के 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, संगठन नहीं, बल्कि एक सोच है, जो लोगों के दिलों में बसी हुई है, यह सोच सदियों से चली आ रही है। यही सोच अशोक में थी, गुरु नानक, गांधी , अकबर में भी थी। यह सोच 3000 सालों से हिन्दुस्तान में नहीं मिटी है और आप इसे नहीं मिटा सकते, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वह अपने आप मिट गया। यहां देखें तो राहुल का वक्तव्य संतुलित और सूझ-बूझ वाला लगता है, पर इसी के साथ उनके ही एक वरिष्ठ सहयोगी अय्यर के बयान को पढ़ने के बाद कोई कैसे सोच सकता है कि अय्यर साहब भी कांग्रेस की तीन हजार साल वाली सोच से ताल्लुक रखते हैं।

इसी सप्ताह मेनका गांधी का भी एक वक्तव्य आया है कि राहुल चिड़ियां हैं और मोदी शेर। यह भी एक हास्यास्पद बयान है। मेनका की छवि आज तक अहिंसक व्यक्ति की रही है।

वे अक्सर बीमार जीव जंतुओं के बचाव के लिए प्रयास करती नजर आती रही हैं, पर उनका यह चिड़िया और शेर वाला बयान बतलाता है कि उनके जेहन में भी गहरी हिंसा की ही भाषा खुदी हुई है। तभी तो वे चिड़िया पर खूंख्वार शेर को तरजीह देती दिख रही हैं। वे भूल गयीं कि अपने हिंसक स्वरूप के चलते शेर-बाघ दुनिया से मिटा दिए गए, उनकी प्रजाति पर संकट है और उनके लिए अभयारण्य बनाने पड़ रहे हैं और चिड़िया हमेशा की तरह चारों ओर चहकती नजर आती है।

ऐसा नहीं है कि खुद मोदी का बयान सूझबूझ वाला होता है, वह भी अक्सर हवाबाजी करते बेसिर पैर की हांकते ही नजर आते हैं, पर अय्यर की इस किस्म की गिरी हुई बातें मोदी के लिए बिना कुछ किए सहानुभूति जुटाएगी। राजनीति एक गंभीर चीज है और इससे भारत के सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी का भविष्य जुड़ा होता है, इसलिए राजनेता कब क्या बोल रहे हैं इसके लिए उनमें जिम्मेवारी का एहसास तो होना ही चाहिए। कोई आदमी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म से आता हो लोकतंत्र में सबके लिए बराबर की जगह है और यही इसकी विशेषता भी है। किसी पर हंसना या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना तो शोहदेबाजी है राजनीति नहीं।

**मंगल के निकट तिरंगा 23-9-2014**

हरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया इसरो का मंगल अभियान अब इतिहास रचने की ओर है। करीब 20 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की लम्बी दूरी तय करने और नौ महीने से भी ज्यादा समय लेने वाला भारतीय मंगलयान 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस परियोजना की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन महत्त्वपूर्ण देशों के साथ खड़ा होगा जिनके पास ऐसी क्षमता है। अब तक मंगल ग्रह पर विभिन्न देशों की ओर से 52 मंगल अभियानों का प्रयास किया गया है जिसमें 26 अभियान ही सफल रहे हैं। इनमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और पूर्व सोवियत संघ के अभियान उल्लेखनीय हैं।

**भाषाओं का मसला 26-7-2014**

घ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सी-सैट के खिलाफ हंगामा जारी है। इसके विरोध में गुरुवार को जहां गुस्साए छात्रों ने पुलिस के वाहनों को आग की भेंट चढ़ा दिया, वहीं मुखर्जी नगर में एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर अपने आपको आग के हवाले करने तक की कोशिश की। परीक्षा पैटर्न में बदलाव की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से ही छात्र संसद भवन के आसपास जमा होने लगे थे। इसके बाद सौ छात्रों को हिरासत में लिया गया और आस-पास के तीन मेट्रो स्टेशनों को एहतियातन बंद कर दिया गया। इस बवाल के बीच कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा, 'सी-सैट 2011 से लागू हुआ है। हम छात्रों की दिक्कतों को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने इस मामले पर एक कमेटी का गठन किया है, जो एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। छात्रों को एडमिट कार्ड जारी किए जाने से घबराने की जरूरत नहीं है।' राज्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि भाषायी भेदभाव स्वीकार्य नहीं है और सरकार छात्रों के हित में काम करेगी।आश्चर्यजनक है कि सत्ता में आने के पहले हर बात पर जमकर बोलने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पिछले चुप्पा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी पीछे छोड़ रहे हैं।

इस मसले पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा हुआ। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कहा कि भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। विपक्ष ने एडमिट कार्ड भी वापस लिये जाने की मांग की है।

देखा जाए तो आजादी के लंबे अरसे बाद भी सिविल सर्विसेज परीक्षा का वर्तमान पैटर्न लगभग वही है, जो अंग्रेजों के समय था। 1989 तक तो इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही था, पर आंदोलन के कारण सन् 89 के बाद सिविल सेवाओं की परीक्षा में अन्य भाषाओं को भी जगह मिल पायी। परीक्षा में हिन्दी और दूसरी भाषाओं को जगह मिलने के बाद भारतीय भाषाओं के छात्र बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवाओं में आने लगे। लेकिन, अंग्रेजी मानसिकता के लोगों ने 2008 से मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के प्रश्नपत्रों को अनिवार्य कर दिया। इससे हिन्दी भाषी छात्रों की परेशानी फिर बढ़ गई। इतना ही नहीं, 2011 में सी-सैट परीक्षा पैटर्न में अंग्रेजी के अंकों को मेरिट में जोड़ने की प्रक्रिया ने हिन्दी माध्यम के छात्रों की कमर तोड़ दी। इस बदलाव के बाद हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों के इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परिमाण लगातार गिरता गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी आरोप है कि नया पाठ्यक्रम विज्ञान के छात्रों के लिए तो आसान है, खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, जबकि मानविकी और हिन्दी व दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के लिए यह कठिन है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी के कठिन प्रश्नपत्र और सी-सैट के कारण वर्ष 2014 में 1100 सफल उम्मीदवारों में से भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले सिर्फ 26 परीक्षार्थी ही पास हो सकें थे, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाले एक हजार से ज्यादा छात्र पास हुए थे। इससे नौकरशाही पर अंग्रेजीदां वर्ग के हावी होते जाने का भय सहज है। सी-सैट के कारण हिन्दी माध्यम से सफल होने वाले छात्रों की संख्या साल 2010 के 35.6 प्रतिशत से घटकर अब 15.3 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार के भाषाई भेदभाव से अपने ही देश के बड़े तबके की शासन चलाने में भागीदारी खत्म होती जाएगी और मुल्क फिर से भाषायी गुलामी की ओर बढ़ता चला जाएगा।

**और क्या होंगे अभी 24-7-2014**

म कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।' कभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने आम भारतीयों की मानसिकता को लेकर ये पंक्तियां लिखीं थीं। औसत भारतीय अक्सर अपनी सहिष्णुता की संस्कृति पर गर्व करना चाहता है, पर हमारे कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों का आमजनों के साथ जिस किस्म का घमंड और असहिष्णुता से भरा व्यवहार सामने आ रहा है, वह देश और विदेशों में हमारी छवि खराब करने वाला और शर्मिंदगी पैदा करने वाला है। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के ग्यारह सांसदों का जिस किस्म का वहशीपन सामने आया, वह ऐसा ही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र सदन में मराठी व्यंजन न परोसे जाने से सांसद इतने नाराज हो गए कि इसकी खुन्नस उन्होंने कैटरिंग में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाले अरशद के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूंसकर निकाली। अरशद उस समय रोजे में थे।

जब संसद में कांग्रेस ने यह मामला उठाया तो इस पर जमकर हंगामा हुआ, यहां तक कि सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। यद्यपि शिवसेना सांसद शुरुआत में आरोपों को खारिज करते रहे, लेकिन एक वीडियो फुटेज सामने आने के बाद उन्होंने यह कहना शुरू किया है कि उनकी मंशा बिलकुल भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। वह रमजान का सम्मान करते हैं। अरशद ने नेम प्लेट भी लगा रखी थी। यूं अगर शिवसेना सांसद यह नहीं भी जानते थे कि कैटरिंग स्टाफ रोजे में है, तब भी वीडियो फुटेज से जाहिर हो रही उनकी हरकतों को मानवीय आधारों पर किस भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है? वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र सदन में हुआ, वह ठीक नहीं था। मुझे लगता है कि इस मामले से जुड़े सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। संसद में विवाद के बाद शिवसेना सांसदों ने मांफी मांगी भी।

शिवसेना का हमेशा से एक अतिवादी वैचारिक नजरिया सामने आता रहा है। बालासाहब ठाकरे की मौत के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि, उद्धव ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी हिन्दुत्ववादी है, लेकिन किसी धर्म की विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने सरकार गठन के पहले और बाद में धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते हुए अवाम को जिस तरह से भरोसा दिलाया था कि उनके जान-माल की रक्षा की जाएगी तो अब सवाल उठता है कि क्या मोदी शिवसेना सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? विपक्षी यह मांग कर रहे हैं कि शिवसेना सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। बसपा नेता मायावती ने शिवसेना सांसदों की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस, एनसीपी ने भी इसे अपराध करार दिया है। जेडीयू नेता अली अनवर ने गृह मंत्री से आरोपी सांसदों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने और सदन से सदस्यता खत्म करने की मांग की है। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने घटना की निंदा करते हुए आग्रह किया है कि इसे तूल न दिया जाए। मोदी सरकार को अल्पसंख्यक अविश्वास की नजरों से देखते हैं। ऐसे में अगर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी जाएगी, तो उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और यह कहीं से भी देशहित में नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को क्या कुछ कर पाती है?

**<u>बहन भाषाएं हिंदी-उर्दू 6-9-2014</u>**

दी-उर्दू जैसी बहन भाषाओं को सांप्रदायिकता की जमीन से देखने वालों को इसे लेकर लोगों में दरार डालने में सफलता नहीं मिली और उच्चतम न्यायालय ने भी 25 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू को प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने को उचित ठहराया। देखा जाए तो कुछ लोगों और संगठनों द्वारा जनता से जुड़े तमाम मसलों को राजनीतिक लाभ-हानि के हिसाब से अवसरवाद की छड़ी से पीटना उन्हें किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने वाली भूमिका ही प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में उर्दू को सरकारी कामकाज की दूसरी भाषा घोषित करने के फैसले पर गुरुवार को अपनी स्वीकृति की मुहर लगाते हुए कहा कि इस देश के भाषाई कानून कठोर नहीं बल्कि भाषाई पंथनिरपेक्षता का लक्ष्य हासिल करने के लिए उदार हैं।

1989 में यूपी सरकार ने यूपी राजभाषा कानून में संशोधन कर उर्दू को प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन को प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना रास नहीं आ रहा। इसके वकील श्याम दीवान का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 345 के प्रावधानों को बारीकी से समझा जाए तो हिंदी के साथ किसी दूसरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्रदेश सरकार ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया है। पर प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद 345 में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी के अतिरिक्त राज्य में एक या अधिक भाषाओं को दूसरी भाषा घोषित करने से रोकता है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे कई राज्य विधानमंडलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों ने हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी है। दिल्ली में हिंदी के साथ पंजाबी और उर्दू को दूसरी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। पीठ ने यहां तक कहा कि अगर कोई भाषाई संगठन राष्ट्रपति के पास जाकर किसी भाषा को राजभाषा के दर्जे में शामिल कराने की मांग करता है, तो राष्ट्रपति चाहें तो सीधे राज्य सरकार को उस भाषा को राजभाषा में शामिल करने का निर्देश दे सकते हैं। इन प्रावधानों को व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए न कि संकीर्ण रूप में।

भाषा को लेकर ऊटपटांग दलीलें देकर आम जन को विभाजित करने वालों को अपनी समझ साफ करने की जरूरत है। हिन्दुस्तान के ख्यातिप्राप्त शायर रघुपति सहाय 'फिराक'अपनी पुस्तक 'उर्दू भाषा और साहित्य'में स्पष्ट लिखते हैं-'ऐसे बीसो हजार उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी शब्दों को एक विशेष ढंग से बोलने या लिखने का नाम उर्दू है। यह ढंग या शैली ही उर्दू भाषा की आधारशिला है।' वे यह भी लिखते हैं-'यह समझना भ्रम होगा कि हिंदी शब्दों में केवल अरबी और फारसी शब्दों को मिला देने से उर्दू बनती है। शत प्रतिशत हिंदी शब्दों से भी बनी हुई उर्दू गद्य और कविता की किताबों में मिलती है।'इसलिए भाषा को किसी जात या जमात से जोड़कर सतही ढंग से देखे जाने से आगे जाकर हमें उसकी जनमत में पसरी जड़ों को पहचानना होगा।

**<u>आस्था-विकास की जुगलबंदी 30-9-2014</u>**

युक्त राष्ट्र महासभा और अमेरिका के मेडिसन स्क्वॉयर पर दिए गए अपने भाषणों के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के बाद तमाम राज्यों में हुए विगत उपचुनावों में मिली लगातार पराजय और चीनी राष्ट्रपति के आगमन के साथ भारत में चीनी सेना की चुमार में दखलअंदाजी से अपनी इमेज को हो रहे नुकसान को खासा सुधारा है।संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर का राग फिर से छेड़ने के बावजूद आतंकवाद और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों की बातें मजबूती से रखकर मोदी ने पाकिस्तान के अड़ियल रुख को भी एक हद तक प्रभावित करने में सफलता पाई है। आतंकवाद के साये में गंभीर द्विपक्षीय वार्ता की पेशकश करते हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच के प्रयोग को भी मोदी ने बेकायदा बताया। दीगर है कि शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की पैरवी की थी। पर, भारत के कड़े रुख के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने माना है कि हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात की टाइमिंग गलत थी।

याद रहे कि इसके विरोध में भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी। अब पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने भी यूएन में मोदी के भाषण की तारीफ करते कहा है, 'मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो सकारात्मक बात लगी, वह यह कि मोदी पाकिस्तान समेत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारना चाहते हैं।'

विगत लोकसभा चुनावों में संकीर्ण रवैये वाले अपने कुछ सहयोगियों की सरकार बनने के बाद की विध्वंसक टिप्पणियों को बिसराते हुए मोदी जिस तरह एक व्यापक परिपेक्ष्य में बात करने की कोशिश में हैं, वह उनकी बेचैनी भी दर्शाती है। जिन किन्हीं के सहयोग से सत्ता में आने के बाद वे उसके गुलाम और मोहरे की तरह काम करते नहीं दिखना चाहते और प्रयास में हैं कि उनकी एक सकारात्मक छवि बने। इस क्रम में जहां-तहां उनकी जबान भी फिसलती दिखती है और साल व दशक के फर्क को भूलकर जोश में कुछ का कुछ बोल दे रहे हैं।यहां तक कि वे सपेरों का देश आदि मुहावरों को भी उचित परिपेक्ष्य में नहीं रख पा रहे। फिर भी उनकी कोशिश लीक पीटने की कम से कम नहीं दिखती है और अपने चाणक्यों को किनारे करते हुए वे औरंगजेब का खिताब पाकर भी अगर झुकने के बजाय देश-विदेश में बुलंदी से अपने सपनों का इजहार कर पा रहे हैं तो लोगों को इंतजार करना चाहिए। हालांकि, अपनी परंपरावादी टीम के साथ एक दशक बाद सबको घर मुहैया कराने जैसे सपनों को पूरा कर दिखाना आसान नहीं है, पर उनका जज्बा और आम भारतीय युवा पर अपनी निगाहें केंद्रित करने को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूं यह बात एक कठिन सवाल की तरह उनके सामने बारहा आएगी कि लव जिहाद जैसे सतही मसलों में अपनी ताकत खपाने को आतुर उनके पीछे चलने वाला युवा क्या उनके विकास के लिए आंदोलन जैसी शब्दावली को समझने को कभी तैयार हो पाएगा? आस्था के साथ विकास की जुगलबंदी को वे कब तक और कहां तक साध पाते हैं, यह समय ही बताएगा।

**योगी का अवसरवाद 13-9-2014**

गर हमारे रहनुमा ही तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए विद्वेष फैलाने वाला भड़काऊ भाषण देने लगें और कानूनी प्रतिबंधों को किनारे कर सभाएं करने लगें तो आम जनता को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सीख कौन देगा? अब जब भाजपा के फायरब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ पर उपचुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के चलते गौतम बुद्ध नगर में एफआइआर दर्ज की गई हो तो फिर आम जनता की शांति के स्वप्न के बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है। आदित्यनाथ के खिलाफ 24 घंटे में दो एफआइआर दर्ज की गई हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क के किसी भी रहनुमा के लिए इसे कोई जीत का तमगा तो माना नहीं जा सकता। संसद में दागी राजनेताओं के सवाल पर पहले से ही बहस होती रही है और उच्चतम न्यायालय ने इसे लेकर मोदी सरकार को अपनी पहल पर दाग धोने को प्रेरित भी किया है, पर योगी और अमित शाह आदि के भड़काऊ वक्तव्यों को देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को न्यायालय की सलाह की कोई परवाह है। अगर ऐसा होता तो वह अपने इन नेताओं को नियंत्रित करने की पहल करती बजाय उन्हें उपचुनावों में उत्तरप्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि बना देने के।

**9/11 और अमेरिका 12-9-2014**

मेरिका ने एक बार फिर दुनिया से आतंकवादियों का नामोनिशां मिटा देने का इरादा व्यक्त किया है। 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन के निर्देशन में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले के बाद भी अमेरिका ने ऐसे इरादे व्यक्त किए थे और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में वर्षों कार्रवाई की थी। 13 बरस पहले के अल कायदा का नामोनिशान तो नहीं मिटा, उससे भी ज्यादा क्रूरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम देने वाला आइएसआइएस अब दुनिया के सामने है।

**जिन्दा कौमों का इंतजार 11-8-2014**

जपा की राष्ट्रीय परिषद के संबोधन भाषण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तासीन होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मात करने वाली बनती जा रही अपनी मौनी बाबा की छवि को तोड़ते हुए फिर से लोकसभा चुनावों के पहले का बड़बोली जुबान वाले राजनेता का चेहरा धारण कर लिया है। चुनावों के बाद आलू, टमाटर, रेलभाड़ा आदि के बढ़ रहे दामों से त्रस्त आमजन के सामने एक बार फिर उन्होंने 'हम गरीबों को आगे रखकर निर्णय करें तो कठोर से कठोर मानदंडों पर खरे उतरेंगे' जैसे नारे को उछालना आरंभ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक उन्हें गरीब जनता के दुखों का इलहाम हो गया हो या चुप्पी का व्रत उन्होंने तोड़ डाला हो। इंदिरा गांधी ने भी 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे का अरसे तक प्रयोग कर आमजन की दबी हुई आकांक्षाओं का दोहन कर सत्तासुख प्राप्त किया था, मोदी भी उसी राह पर हैं। यह सब आगे आने वाले राज्यों के चुनावों की तैयारी के तहत सोच-समझ कर किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद उत्तराखंड में हाल में हुए तीन सीटों पर उप चुनावों में जैसी मात भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लगता है उससे उनके रहनुमाओं का कंठ फिर से फूटा है और गरीब, राष्ट्र, कांग्रेस आदि का जाप आरंभ कर दिया गया है।

अपने संबोधन में भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह ने भविष्य में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का आह्वान करते हुए

देश को 'कांग्रेस-मुक्त' करने का नारा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य दलों पर वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मोदी ने विश्व में भारत का डंका बजने की बात भी कही। शाह ने पिछले छह दशकों से देश में छायी कांग्रेस की विचारधारा की जगह अपनी विचारधारा को प्रभावी बनाने का आह्वान भी किया है।

देखा जाए तो शाह के कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तानाशाही शासन की आकांक्षा को ध्वनित करता है, ना कि स्वस्थ लोकतंत्र की कामना को। किसी पार्टी विशेष से देश को मुक्त करने की मांग को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। यह एक तरह से विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की मांग जैसा है। जब जनता ने आपको बहुमत देकर सत्ता में ला दिया और कांग्रेस को सिमट जाने को मजबूर कर दिया, तो अब कौन सा डर है जो आपको इस तरह की निरंकुश मुक्ति के नारे को उछालने को प्रेरित कर रहा है। बहुमत में आ जाने के बाद भी अगर आप आमजन के उपयोग की सामग्री की कीमतें बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं और हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़े मुद्दों पर आंदोलित भारतीय युवाओं की चीख-पुकार को अनसुना कर विदेशों में अपनी छवि चमकाने को ही अपना परम लक्ष्य बना ले रहे हैं तो आपको भारत का गरीब गुरबा अपना रहनुमा समझने की भूल कब तक करता रहेगा? चुनावों के पहले आप पांच वर्ष की मांग कर रहे थे, अब आप 60 साल बनाम 60 दिन का शिगूफा छोड़ रहे हैं। तर्क यह कि कांग्रेस ने 60 साल में जो किया, उसे रास्ते पर लाने के लिए आपको भी समय चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया को भाजपा अक्सर साथ-साथ याद करती है, तो भाजपा लोहिया का यह कथन भी याद रखे कि जिन्दा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं।

**बहस की नई जमीन 18-10-2014**

र राज्यों में हुए उप चुनावों के नतीजों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का खूंटा-खेमा जिस तरह से उखड़ता और हवा होता दिखा है उसने उसके विपक्षियों को तो नये सिरे से बहस की जमीन दी ही है इसके साथ ही उसके पुराने राजनीतिक साथियों ने भी अब अपना रंग दिखलाना शुरू कर दिया है। इससे भारतीय राजनीति में चल रही बहसों का रुख बदलता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में देश के साथ-साथ महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की बी टीम बनकर नहीं रहना चाहती थी। भाजपा की इस मंशा को अस्वीकार करते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा था कि ज्यादा सीटों की वासना से तलाक हो जाता है। शिवसेना के अनुसार मोदी लहर कई राज्यों में असर दिखाने में असफल रही है और हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय केवल मोदी को नहीं बल्कि उनके गठबंधन सहयोगियों को भी दिया जाना चाहिए। सामना में छपे लेख पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा था कि नपुंसकता भी तलाक की वजह बन सकती है। पर कल के उप चुनावों के परिणामों ने शिवसेना का मनोबल फिर से बढ़ा दिया है उसने अपने मुखपत्र में भाजपा को चेतावनी देते हुए लिखा है कि वह अपने पैर को जमीन पर रखे नहीं तो जनता चमड़ी उधेड़ देगी।

शिवसेना प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए लव जिहाद के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उसका कुछ विशेष परिणाम नहीं दिखाई देता।

स्पष्ट है कि एक-दूसरे की छीछालेदर करते भाजपा और शिवसेना के ये बयान दोनों दलों के ढाई दशक पुराने रिश्तों को अनुकूल तो नहीं ही बनाएंगे, इससे भविष्य में इनकी दूरियां और बढ़ेंगी ही। उप चुनाव में भाजपा की हार पर 'शॉटगन' शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने गोले दाग दिए हैं। इस हार के लिए पार्टी द्वारा उसके वरिष्ठ राजनेताओं को किनारे करने की नीतियों पर हमला करते हुए सिन्हा ने पार्टी हाईकमान से वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में वापस मुख्य भूमिका में लाने की मांग की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अनुभवी नेताओं को किनारे लगाए जाने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। सिन्हा ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि राजनीति में व्यक्ति 50-60 साल के बाद परिपक्व होता है।

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कई ऐसे नेता हैं जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, शत्रुघ्न सिन्हा का इशारा उसी तरफ है। हालांकि यह एक हद तक सही भी है कि अनुभवी लोगों को हटाने से भाजपा की मजबूत दीवार दरकी तो है। इस दरकती जगह को भरने के लिए पार्टी को नए सिरे से और मजबूती से 'चिनाई' करनी होगी।

भाजपा-शिवसेना की अंदरूनी मारामारी के बाद अब कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन भी विवादों में खिंचा चला आ रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कह दिया है कि कांग्रेस को उसके मुताबिक सीटों पर लड़ने नहीं दिया जाएगा। एनसीपी में जब से आठ निर्दलीय विधायक शामिल हुए हैं, तभी से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के तेवर बदले से हैं। उन्होंने खुलकर कांग्रेस को कम सीटों पर ही चुनाव लड़ने की हिदायत दे डाली है।

वहीं अभी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया है, पर इन उप चुनावों में धूल झड़कर उठ खड़ी होने की कोशिश करती कांग्रेस का रुख भी अब बदले तो आश्चर्य नहीं।

**सत्ता के समीकरण 3-10-2014**

ह मान्य तथ्य है कि सत्ता व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के चरित्र और व्यवहार में एक निर्णायक परिवर्तन करती है। सत्तासीन व्यक्ति सत्ता से मिली ताकत और उसके प्रक्षेपणों से बन रही छवि के बीच तालमेल करता हुआ पुराने चले आ रहे तमाम समीकरणों को धीरे-धीरे बदलता चला जाता है और उसके अंतरविरोध नई परिस्थितियों में खुद को नये ढंग से पुनर्परिभाषित करने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे परिवर्तनों और अंतरविरोधों को हम इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। विगत लोकसभा चुनावों के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि महाराष्ट्र में दशकों से चला आ रहा भाजपा और शिवसेना का संग-साथ इस तरह बिखरता चला जाएगा। यूं कल्पना तो इसकी भी नहीं की जा सकती थी कि भाजपा अपनी राजनीति के वर्तमान पितामह लालकृष्ण आडवाणी को इस तरह किनारे कर चुनावों में जीत हासिल करेगी। पर, आडवाणी के बिना मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और आज आडवाणी को भी मोदी की प्रशंसा करनी पड़ रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते कहा है कि नरेंद्र भाई जिम्मेदारी की भावना के साथ काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्हें प्रशंसा मिल रही है। हालांकि, उन्होंने मोदी की प्रशंसा करते हुए अटल को जिस प्रमुखता से याद किया है, उससे लगता है कि उनके जख्म भर नहीं रहे हैं।

आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में वाजपेयी जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वाजपेयी को जो सम्मान मिला, उसकी दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार थे। हाल ही में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से हटा कर भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया था जिसे आलोचकों ने मूकदर्शक मंडल की संज्ञा से नवाजा है।

बहरहाल वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा-शिवसेना गठबंधन टूटने का भी मलाल है। हालांकि, महाराष्ट्र भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि शिवसेना के अड़ियल रवैये के चलते गठबंधन टूटा। पर, शिवसेना ने इस टूट का ठीकरा नए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर तोड़ते हुए कहा है कि उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह से महाराष्ट्र चुनाव तक पार्टी प्रमुख की कुर्सी संभालने को कहा था और यदि वह ऐसा करते तो आज गठबंधन नहीं टूटता। टूट के संदर्भ में उद्धव के राजनाथ सिंह के अलावा सुषमा स्वराज और आडवाणी के प्रति भी सकारात्मक उदगार हैं। राजनाथ की प्रशंसा में उद्धव ने यह भी कहा कि वह एक ऐसे नेता हैं, जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में यूपी के तमाम करिश्मे के बावजूद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह किसी को भा नहीं रहे। उधर, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बातों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भी इस्तीफे से इनकार करते दिख रहे हैं। यहां हम साफ देख सकते हैं कि पार्टी के उपेक्षित और किनारे किए जा रहे नेता पार्टी के बाहर सहानुभूति का रवैया तलाश रहे हैं और वह उन्हें मिल भी रहा है। यह नई प्रवृति भविष्य में राजनीति की नई रूपरेखा को आकार देने की कोशिश कर सकती है।

ह मान्य तथ्य है कि सत्ता व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के चरित्र और व्यवहार में एक निर्णायक परिवर्तन करती है। सत्तासीन व्यक्ति सत्ता से मिली ताकत और उसके प्रक्षेपणों से बन रही छवि के बीच तालमेल करता हुआ पुराने चले आ रहे तमाम समीकरणों को धीरे-धीरे बदलता चला जाता है और उसके अंतरविरोध नई परिस्थितियों में खुद को नये ढंग से पुनर्परिभाषित करने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे परिवर्तनों और अंतरविरोधों को हम इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। विगत लोकसभा चुनावों के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि महाराष्ट्र में दशकों से चला आ रहा भाजपा और शिवसेना का संग-साथ इस तरह बिखरता चला जाएगा। यूं कल्पना तो इसकी भी नहीं की जा सकती थी कि भाजपा अपनी राजनीति के वर्तमान पितामह लालकृष्ण आडवाणी को इस तरह किनारे कर चुनावों में जीत हासिल करेगी। पर, आडवाणी के बिना मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और आज आडवाणी को भी मोदी की प्रशंसा करनी पड़ रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते कहा है कि नरेंद्र भाई जिम्मेदारी की भावना के साथ काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्हें प्रशंसा मिल रही है। हालांकि, उन्होंने मोदी की प्रशंसा करते हुए अटल को जिस प्रमुखता से याद किया है, उससे लगता है कि उनके जख्म भर नहीं रहे हैं।

**अपराजेय मैरी कॉम 2-10-2014**

च बार की विश्व चैंपियन व ओलंपिक कांस्य विजेता महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने अंततः17 वें एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले से पहले ही किए गए अपनी जीत के ऐलान को सच कर दिखाया। उन्होंने 51 किलोवर्ग में तगड़ा पंच लगा भारत के लिए ना सिर्फ सातवां गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया। उनका मनोबल इतना मजबूत था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत का ही अहसास था। और यह सिर्फ उनकी ही बात नहीं थी, हर भारतीय के मन में जैसे उनकी जीत का अटल विश्वास सा था। मैरी कॉम का आत्मविश्वास जहां भारतीय प्रतिभा के ठोस संकल्पपूर्ण व्यक्तित्व का एक उदाहरण सा है, वहीं इस भारतीय आत्मविश्वास की जड़ में उन पर बनी फिल्म 'मैरी कॉम' की सफलता और उस आधार पर बन रही उनकी जनछवि को भी एक कारक माना जा सकता है। देखें तो ऐसा पहली बार है कि किसी ने अपनी ही फिल्मी छवि को जैसे बीट किया है, जनलोकछवि को एक शिकस्त दी है। पहली बार हुआ है कि किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन को उसके मूल चरित्र ने पीछे छोड़ दिया हो। मैरी कॉम अपराजेय भारतीय जिजीविषा का अनन्य उदाहरण हैं। बिलियर्डस खिलाड़ी गीत सेठी ने सही कहा है कि मैरी कॉम जन्मजात फायटर हैं।

कजाकिस्तान की मुक्केबाज के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले मैरी कॉम ने कहा था कि उन्हें कुछ लोगों को गलत साबित करके दिखाना है और वो जीतकर रहेंगी। यह पांच बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम का एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल था। फिल्म 'मैरी कॉम' में उनके चरित्र को जीने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इस जीत को अहम बताते हुए इसे मात्र एक एथलीट की जीत नहीं, बल्कि महिला वर्ग की जीत कहा है। इसे वे मैरी कॉम की वापसी ना कह कर मानती हैं कि वे कहीं गई ही नहीं थीं। ऐसे समय में जब दुनिया भर में और खासकर भारत और उसमें भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा का उफान सा है और महिला व्यक्तित्व निर्माण एक तरह के संकट के दौर से गुजरता सा दिख रहा है, मैरी कॉम की यह वैश्विक सफलता जीवन की दौड़ में हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करती जा रहीं महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सा है। मैरी कॉम की जीत धार्मिक अंधविश्वासों और फतवों की बढ़त के मुंह पर भी एक जबरदस्त घूंसा है कि विकसित हो चुकी और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली इस जाति को फिर से घर तक सीमित करने की कोशिशें अब सफल नहीं होने वाली।

अपनी जीत पर मैरी कॉम ने कहा, 'मेरे लिए इस मेडल के कई मायने हैं। मैं सरिता के आंसू नहीं देख पा रही थी। उनके साथ हुए अन्याय का प्रतीकात्मक बदला लेने के लिए मैं हर हाल में गोल्ड जीतना चाहती थी। साथ ही मैं अपने तीन बच्चों- रेचुंगवर, खापूनीवर और प्रिंस चुंगथानग्लेन कॉम के लिए मेडल जीतना चाहती थी।' इस तरह देखें तो मैरी कॉम की यह जीत बहुआयामी है, जिसमें अपने देश के लिए जीत का जज्बा है तो परिवार में ममत्व की छांव से दूर पल रहे बच्चों की पीड़ा के लिए मरहम भी है। और तो और गलत ढंग से पराजित ठहराई गई अपनी साथी की हार का बदला चुकाने की एक सकारात्मक जिद भी। यह सशक्त महिला चरित्रों के अभ्युदय का युग है और मैरी कॉम इस युग का एक बेमिसाल उदाहरण हैं।

**<u>भाजपा का मूकदर्शक मंडल</u>**

रतीय जनता पार्टी की त्रिमूर्ति कही जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड में जगह नहीं देने और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पर घूस लेने के आरोपों और उस पर राजनाथ और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी जा रही सफाई को लेकर चर्चा का बाजार जिस तरह गर्म है, वह भाजपा के लिए किसी स्वस्थ वातावरण के निर्माण की पहल को नहीं दर्शा रहा है। खासकर उन हालातों में जबकि विगत आम चुनावों में मिली जीत के बाद उत्तराखंड और बिहार आदि में हुए उपचुनावों में पार्टी को लगातार मुंह की खानी पड़ी हो। अटल-आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में स्थान देकर सम्मान के साथ यह भी जता दिया ा सके। सीपीआइ नेता अतुल अनजान ने वाजपेयी और आडवाणी के बिना बने इस संसदीय बोर्ड को आरएसएस का बोर्ड कहा है। अनजान ने सवाल सबसे प्रधानमंत्री की नो नॉनसेंस प्रधानमंत्री वाली छवि धूल-धूसरित हुई है और संपूर्ण सत्ता के 100 दिन पूरे करने जा रही एक पार्टी के लिए यह कहीं से शुभ नहीं है।

**<u>साधो, देखो जग बौराना 27-8-2014</u>**

धो, देखो जग बौराना। सांची कही तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। हिन्दू कहत, राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दौऊ लड़ै मरत हैं, मरम कोउ नहिं जाना।' गत 24 तथा 25 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के गृहनगर कवर्धा में द्वारकापीठ के शंकराचार्य के बुलावे पर आयोजित कथित धर्म संसद में जिस तरह से कुछ साधु, संतों तथा धार्मिक अखाड़ों के सरगनाओं ने आपस में धक्का-मुक्की करते हुए सनातन धर्म के नाम पर कुछ फैसले लिये, उसे देखते हुए कबीर की उपरोक्त पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं। धर्म संसद ने ऐलान किया कि शिरडी के संत साईंबाबा को संत, गुरु या भगवान कहकर उनकी पूजा करने पर रोक लगे और तमाम मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटायी जाएं। यह विडंबना ही है कि धर्म संसद बुलाने का मध्यकालीन शोशा जिस शहर में छोड़ा गया है, उसका नाम छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीर नगर रखा है। देखा जाए तो धर्म संसद में इस तरह से किसी को भगवान मानने या न मानने का फैसला पश्चिम में धर्म के नाम पर चल रही गतिविधियों से प्रभावित दिखता है। पश्चिम में ही लोगों को संत आदि का टैग देने की प्रथा है जिसके लिए वहां विविध प्रकार के इम्तिहान और मापदंड भी पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। आलम यह है कि पश्चिम में अनेक संत अपने प्रभावी व्यक्तित्व के बावजूद सिर्फ इसलिए संत बनने से चूक गए क्योंकि वे कथित परीक्षाओं को पास नहीं कर सके। बहरहाल, हिन्दुस्तान में तो भगवान भाव का पद है, जो जन-जन के मन में बसता है। इसी तरह से यहां तैंतीस करोड़ देवता बने हैं। साधुओं की जमात किसी को भगवान घोषित करे या लोगों द्वारा भगवान माने जा रहे किसी व्यक्ति अथवा संत को भगवान के पद से नीचे उतारे, ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है। यहां तो फिल्मों से देवता पैदा होते देखे गए हैं। 'जय संतोषी मां' फिल्म के आने के बाद किस तरह गांव-गांव में संतोषी माता की पूजा होने लगी थी, उसे कोई भी याद कर सकता है। यह और ऐसे तमाम प्रकरण तय करते हैं कि भारत में भगवान लोगों की आस्था से पैदा होते हैं, संतों की जुटान में लिये गए फैसलों से नहीं। फिर समय-समय पर ये भगवान बिसार भी दिए जाते हैं। सो साईं आज जो कुछ हैं, वह लोगों की आस्था की उपज हैं और कब उनके मानस से उन्हें बाहर होना है, यह समय ही तय करेगा, समय की दया पर निर्भर क्षणभंगुर देह धारण करने वाले साधु-संत नहीं। यहां हम फिर कबीर का उदाहरण ले सकते हैं - तैंतीस कोट देवता मरिहैं, बड़ी काल की बाजी। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई।

**<u>बिहार में दलित उत्पीड़न 1-10-2014</u>**

लित उत्पीड़न को लेकर बिहार चर्चा में है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तक उत्पीड़न की अपनी व्यथा को मंचों से जाहिर कर रहे हैं। मांझी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ शक्तिशाली लोग मुझे अछूत मानते हैं क्योंकि मैं एक महादलित हूं। कुछ लोगों ने उनके महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देव प्रतिमा को धोया। उन्होंने कहा कि लोग अपना काम निकलवाने के लिए उनके पांव छूते हैं, लेकिन जब बात सामाजिक स्तर पर आती है तो वे उन्हें अछूत की तरह ही लेते हैं। हालांकि, इस बयान का खंडन मंडन हो रहा है, पर मुख्यमंत्री की भाषा में उनके महादलित होने की पीड़ा और जातिगत पाखंड की जड़ों को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री मांझी के पहले के कई बयानों को भी विवादित बताया जाता रहा है, पर अगर हम उनके बयानों पर गौर करें तो पाएंगे कि वह बयान एक महादलित परिवार से आने वाले व्यक्ति की सहज अभिव्यक्तियां हैं। मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई का पात्र माना गया था कि उन्होंने एक दलित को आगे किया, भले ही इसके पीछे दलित कार्ड चलने का दबाव हो। देखा जाए तो सवर्ण सत्ता का आदी हमारा मीडिया एक महादलित के वक्तव्यों को उनकी जबानी फिसलन बताते हुए उसकी अपनी व्याख्याएं करता नजर आता है। दानापुर में बासगीत का पर्चा बांटते समय जीतनराम मांझी ने कहा था कि दारू को दवा के रूप में पीएं, इससे समस्या नहीं होगी। दीगर है कि नशे के कारण महादलित लोग न तो अपने बच्चों का ध्यान रख पाते हैं, न ही जीवन को बेहतर कर पाते हैं। पर, मीडिया ने इसे इस रूप में प्रचारित किया कि मांझी दारू या शराब पीने की वकालत कर रहे हैं। जबकि मांझी स्पष्ट रूप से दवा-दारू मुहावरे के संदर्भ में दारू को दवा की तरह पीने की बात कर रहे थे। हवाई राजनीतिक बातों के विषेण के आदी मीडिया को यह कैसे बर्दाश्त होता कि एक महादलित परिवार से आया व्यक्ति संयम की बात करे। संयम का ठेका तो सवर्ण जाति के महाप्रभुओं के जिम्मे है। मीडिया को यह याद नहीं रहा कि सुशासन बाबू के नाम से चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद शराब की दुकानों पर बैठकर पीने को वैध करार दिया था। तब इस जनविरोधी फैसले के लिए नीतीश की तो इतनी फजीहत नहीं हुई थी।

बिहार के ही गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र स्थित पुरा गांव के करीब तीन सौ महादलित परिवार डरे-सहमे हैं। दबंगों से भयभीत एवं दहशतजदा महादलित परिवार बच्चों और जानवरों के साथ गांव छोड़ गए हैं और वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। यह केवल बिहार की बात नहीं है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सब जगह यही हाल है। पिछले ही साल गुजरात के गांव गलसाना में दलितों को बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। मंदिरों में प्रवेश की लड़ाई लड़ने के कारण डेयरी वालों ने दलितों को दूध और बाकी चीजें देने से भी मना कर दिया था। सवाल इस बात का है कि जन आंदोलनों और जन भागीदारी का आह्वान करते हुए जिस भारत की प्रगति के दुनिया भर में डंके पीटे जा रहे हैं, आखिर वह कब जाति-बिरादरी के प्रपंचों से बाहर निकलकर भाईचारे के पथ पर आगे बढ़ पाएगा?

**चिरयुवा जोहरा का जाना 12-7-2014**

रतीय सिनेमा जगत की लाडली और सबसे बुजुर्ग अभिनेत्री, भारत सरकार द्वारा पद्मर्शी, पद्मभूषण और पद्मविभूषण खिताबों से नवाजी जा चुकीं नृत्य निर्देशक जोहरा सहगल गुरुवार को आखिर नहीं रहीं। जोहरा जैसा जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वह सारी उम्र सक्रिय रहीं और एक्ट्रेस शब्द को उन्होंने अपने जीवन में कुछ इस तरह उतारा कि नई पीढ़ी के नौजवानों के लिये वह प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनी रहीं। वर्ष 2012 में जोहरा सहगल ने जब 100 साल पूरे किए थे, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें 100 साल की बच्ची संबोधित करते कहा था कि जोहरा एक छोटी सी बच्ची की तरह हैं और इस उम्र में भी उनकी असीमित ऊर्जा देखते बनती है। चीनी कम के सैट पर जोहरा हमेशा सबको बड़े प्यार से पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं। खुद जोहरा सहगल कहती थीं कि उनकी लंबी उम्र का राज लंबे समय तक सक्रिय रहना है, अगर आप निष्क्रिय होकर घर पर बैठ गए तो समझ लीजिए आप खत्म हो गए।

विलक्षण प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर जोहरा सहगल ने फिल्मी दुनिया के विख्यात कपूर खानदान की चार पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर के साथ काम किया था। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने जोहरा के निधन पर कहा, वह अपनी शतरें पर जिन्दगी जीने वाली महिला थीं। देखा जाए तो यह अपनी शतरें पर जिन्दगी जीना ही उनकी असीमित ऊर्जा और चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली मीठी सी मुस्कराहट का राज था। पारम्परिक मुस्लिम घराने में जन्मी तथा घोर पर्दा प्रथा में पली-बढ़ीं जोहरा को रूढ़ परम्पराएं बांधकर नहीं रख सकीं। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर सहारनपुर में 27 अप्रैल 1912 में जन्मी साहबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्ला खान र्जमनी के ड्रेस्डेन में मैरी विगमैन्स बैले स्कूल में बैले की शिक्षा ग्रहण करने वाली पहली भारतीय थीं। यूरोप टूर के दौरान उदय शंकर की नृत्य नाटिका 'शिव पार्वती' से प्रभावित होकर वह उदय से मिलीं और उनके साथ जापान टूर पर गयीं। वहां से भारत लौटने पर जोहरा की मुलाकात युवा वैज्ञानिक, चित्रकार एवं नर्तक कामेश्वर सहगल से हुई। घर, परिवार के घोर विरोध के बावजूद 14 अगस्त 1942 में उन्होंने कामेश्वर से विवाह कर लिया। कामेश्वर और जोहरा विभाजन के बाद मुंबई पहुंच गए थे, जब आजादी का जुलूस निकला तो जोहरा सारी रात सड़कों पर जुलूस के साथ नाचती रहीं। उस समय फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें भारत की इसाडोरा डंकन कहा था।

जोहरा सहगल पृथ्वी थियेटर और भारतीय जन नाट्य संघ 'इप्टा' से भी जुड़ी रहीं। अभिनय की बारीकियां उन्होंने अपने पहले प्यार थियेटर से ही सीखीं और उसे ताउम्र संवारने के लिये जद्दोजहद में पीछे नहीं हटीं।अपने करियर की शुरुआत उन्होंने वर्ष 1946 में इप्टा के सहयोग से बनी ख्वाजा अहमद

अब्बाद निर्देशित पहली फिल्म धरती के लाल से की थी। बलराज साहनी ने भी बतौर अभिनेता अपने करियर का आगाज इसी फिल्म से किया था। अपने करियर के दौरान हिन्दी के अलावा कई अंग्रेजी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। बीबीसी द्वारा बनाए गए पड़ोसी (1976-77) धारावाहिक से उन्हें काफी नाम मिला। 1984 में सीरियल 'ज्वैल इन द क्राउन' में लेडी चटर्जी का रोल उनके करियर का चरम बिंदु था। 'तंदूरी नाइट्स' (1985-87) में वे दादी के रोल में थीं और लंदन का हर छोटा-बड़ा दर्शक उन्हें पहचानता था। यह विडंबना ही है कि आजीवन सक्रिय रहीं इस सुख्यात अभिनेत्री ने अपने अंतिम वर्षों में सरकार से एक फ्लैट की मांग की थी, जिसे वे मन में लिये ही चली गयीं।

**चिड़ियाघर में सुरक्षा 18-6-2014**

ल्ली के चिड़ियाघर में सफेद बाघ को देखने आया एक युवक बाड़े में गिरकर बाघ का शिकार हो गया। मकसूद नामक इस युवक की दर्दनाक मौत के बाद चिड़ियाघरों में हिंसक जानवरों के चंगुल में अचानक आ जाने के बाद अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों को लेकर सवालों का उठना वाजिब है। आखिर यह देश की राजधानी दिल्ली के एक चिड़ियाघर में घटी घटना है, जिसके संसाधनों के मामले में सबसे बेहतर होने की आशा सहज ही की जाती है। पर, जिस तरह से बाघ के सामने गिर जाने के दस-पंद्रह मिनट बाद भी उसके बचाव की कोई कोशिश नहीं की जा सकी, उसे लेकर चिड़ियाघर की हास्यास्पद व्यवस्था पर स्वत: प्रश्नचिह्न् लग जाते हैं। वस्तुत: दस मिनट तक वहां चिड़ियाघर का कर्मचारी उपस्थित ही नहीं था, जो ऐसी परिस्थितियों में किए जाने वाले उपायों को आजमाता। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सामने पड़ने पर भी बाघ कुछ देर हमला करने की जगह उसे देखता रहा और बाहर से किसी के पत्थर फेंकने से नाराज होकर उसने मकसूद पर हमला किया। यह बात और चिंताजनक है कि वहां की भीड़ को गाइड करने वाला कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जो ऐसी विकट परिस्थिति में उचित उपाय बताता और पत्थर आदि फेंके जाने से भीड़ को रोकता। हाल में बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चिड़ियाघरों में भी इसी तरह से अचानक बाघ के सामने पहुंच गए लोगों के बारे में पता चलने पर चिड़ियाघरों के कर्मचारियों और दर्शकों ने शोर कर बाघ को उसके शिकार से दूर करने में सफलता हासिल कर ली थी। पर, यहां ऐसा कुछ नहीं किया जा सका।

**गरीबी में अव्वल भारत 18-7-2014**

युक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के सर्वाधिक करीब एक तिहाई गरीब रहते हैं। यह विडंबना ही है कि एक ओर जहां विश्व के रईसों की सूची में भारत के उद्योगपतियों की संख्यां बढ़ती जा रही है, वहीं देश में गरीबी अपना जबड़ा पूर्ववत फैलाए हुए है। ग्लोबल फर्म वेल्थ एक्स की पिछले साल आयी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स देशों में एचएनआइडब्ल्यू की र्शेणी में आने वाले धन कुबेरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा भारत में हुआ और बीते साल देश में एचएनआइडब्ल्यू र्शेणी के धन कुबेरों के क्लब में 120 नए सदस्य शामिल हुए, जो कि अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में सर्वाधिक है। भारत के धनकुबेरों और गरीबों के बीच भारी विषमता को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि भारत में आय वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तथा ज्यादातर संपदा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित होती जा रही है। यह कितना शर्मनाक है कि चीन से तो हम पीछे हैं ही बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देश में भी गरीब भारत से कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के समस्त निर्धनतम लोगों का 32.9 फीसदी हिस्सा भारत में रहता है।

सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सहस्त्राब्दि सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने 2015 तक के लिये गरीबी, भूख, लैंगिक समानता, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों से संबंधित आठ लक्ष्य तय किए थे। जाहिर है कि जिस देश की एक तिहाई जनता घोषित रूप से गरीब हो, वहां इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान काम नहीं है। वर्तमान मोदी सरकार के लिये यह गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि मानव विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है और वह समावेशी तरीके से सभी का विकास करना चाहती हैं। पर, समस्या यह है कि मनमोहन-मोंटेक की जोड़ी ने भी देश में समावेशी विकास की बात की थी, इसके बावजूद एक दशक बाद स्थिति यह है कि हम बांग्लादेश और नाइजीरिया से भी बुरे हाल में हैं। तब मोदी सरकार से यह आशा कैसी की जा सकती है कि मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों पर चलकर वह गरीबों के हित में कुछ नया और उल्लेखनीय कर पाएगी? हालांकि, 1991 से 2010 के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया में गरीबी की दर में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2014 के अनुसार दक्षिण-पूर्वी एशिया में गरीबी दर 1990 के 45 फीसदी से घटकर 2010 में 14 फीसदी रह गई है। पर, भारत की इसमें कोई अच्छी भूमिका नहीं रही और वह अपने एशियायी साथियों से इस मामले में पीछे ही रहा। यह बात और है कि गरीब घटाने के बजाय सारा जोर अमीर बढ़ाओ पर लग गया। नतीजा सामने है।गरीबी हटाओ का नारा देकर ही 71 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। मोदी ने भी चुनावों में खुद को गरीब तबके से जोड़ने की काफी कोशिश की थी। अब देखना है कि इस मुददे पर उनकी सरकार खुद को इंदिरा गांधी की सरकार से कितना अलग कर पाती है?युक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के सर्वाधिक करीब एक तिहाई गरीब रहते हैं। यह विडंबना ही है कि एक ओर जहां विश्व के रईसों की सूची में भारत के उद्योगपतियों की संख्यां बढ़ती जा रही है, वहीं देश में गरीबी अपना जबड़ा पूर्ववत फैलाए हुए है। ग्लोबल फर्म वेल्थ एक्स की पिछले साल आयी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स देशों में एचएनआइडब्ल्यू की र्शेणी में आने वाले धन कुबेरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा भारत में हुआ और बीते साल देश में एचएनआइडब्ल्यू र्शेणी के धन कुबेरों के क्लब में 120 नए सदस्य शामिल हुए, जो कि अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में सर्वाधिक है। भारत के धनकुबेरों और गरीबों के बीच भारी विषमता

को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि भारत में आय वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तथा ज्यादातर संपदा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित होती जा रही है। यह कितना शर्मनाक है कि चीन से तो हम पीछे हैं ही बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देश में भी गरीब भारत से कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के समस्त निर्धनतम लोगों का 32.9 फीसदी हिस्सा भारत में रहता है।

**लालू, नीतीश, मुलायम 14-8-2014**

लू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह और मायावती के साथ मिलकर भारतीय राजनीति में मंडलवादी एकजुटता के युग की वापसी की कोशिशों में जुटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, मायावती ने यह कहकर एक झटके में इस कोशिश को किनारे कर दिया कि मुलायम के लिए सत्ता सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए मान-सम्मान। लालू-नीतीश जोड़ी के जैसे मुलायम-मायावती को भी एकजुट होने का गुरुमंत्र देने पर मुलायम तो मंत्रमुग्ध हो गये थे, उन्होंने मायावती के सामने एकजुट होने का प्रस्ताव रख दिया था। यूं मुलायम की पहल को गंभीर नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह पहल मीडिया के माध्यम से की गई थी। संभवत: इसके पीछे मुलायम को मायावती से ऐसे ही जवाब का भय होगा। मुलायम अगर गंभीर होते तो पहले आपसी सहमति बनाते फिर एलान करते। बिहार में भी जब लालू-नीतीश के एका की बात मीडिया में उठी थी तो लालू ने इससे इनकार किया था, फिर भीतर-भीतर बातें आगे बढ़ीं और उनमें एका हुई। इस लिहाज से अभी भी आशा की जा सकती है कि मुलायम के भीतर पैदा नरमी को जनहित में एक सकारात्मक मौके की तरह देख मायावती खुद को 'मुलायम' करें। यूं उदितराज और रामविलास पासवान की दलित राजनीति आज जिस स्थिति में है, उससे चाहें तो मायावती सबक ले सकती हैं कि व्यक्तिवादी एजेंडे आखिर कहां और किस स्तर तक आम जन की राजनीति को, चाहे वे दलित हों या पिछड़े, आगे बढ़ा सकती है।

**एग्जिट की पोल 14-5-2014**

मवार को सोलहवीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों के लिए मतदान की समाप्ति के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा और राजग के पक्ष में दिख रहे हैं उससे मोदी लहर के पक्षधर गदगद हैं, पर अगर हम पिछले दो- तीन आम चुनावों के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजों के आइने में इस बार के परिणाम को देखें तो 16 मई को आने वाले असली चुनाव परिणाम अभी बल्लियों उछलने वालों को हताश भी कर सकते हैं। 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल के आंकड़े दर्शाते हैं कि इनमें हमेशा ही भाजपा वाले गठबंधन राजग को बढ़ा- चढ़ाकर आंका गया है और कांग्रेस और उसके गठबंधन संप्रग को कम करके देखा गया है। खासकर पिछले दो आम चुनावों 2004 और 2009 के बाद के एग्जिट पोल तो वास्तविक परिणामों से कोसों दूर रहे हैं। पिछले दोनों चुनावों में भाजपा गठबंधन को एग्जिट पोल के आकलन से सौ के करीब सीटें कम आयी थीं।

इस तरह से यह एग्जिट पोल एक तरह से वास्तविक सच्चाई के सामने आने के पहले भ्रम का बाजार खड़ाकर मीडिया के कुछ हलकों द्वारा अपनी चांदी काटने के प्रयासों के सिवा कुछ और साबित नहीं होता। जो एजेंसियां यह सर्वे करवाती हैं क्या उनकी क्षमता पूरे भारत में सक्रिय हो सकने की है या तात्कालिक तौर पर बरगलाने के लिए वे मनमानी घोषणाएं करते हैं। इस पोल में कोई एजेंसी राजग गठबंधन को 237 सीटें दे रही है, तो कोई 340 सीट। भिन्न एजेंसियों के आकलन में जो यह इतनी बड़ी फांक है उसे जनता किस तरह समझे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा भी है कि 80 करोड़ मतदाताओं के देश में कुछ लाख लोगों के नमूना सर्वेक्षण से कैसे नतीजे का अनुमान लगाया जा सकता। एबीपी न्यूज-नीलसन एग्जिट पोल के मुताबिक देश में जहां भाजपा की लहर है वहीं कांग्रेस के खिलाफ एंटी इंकम्बैंसी फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन देश में कम से कम पांच ऐसे बड़े राज्य हैं जहां न तो भाजपा और ना ही कांग्रेस कोई फैक्टर है, बल्कि वहां स्थानीय पार्टियां मुकाबले में हैं। ऐसे में देश में किसी भाजपा लहर की बात करना बेमानी ही है। अगर इन एजेंसियों का यह पोल सही भी है तब भी कोई अखिल भारतीय लहर नहीं है, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में ममता की लहर है वहीं तमिलनाडु में जयललिता की लहर है। ओडिशा में जहां नवीन पटनायक का जादू बरकरार है, तो आंध्र में जगन मोहन रेड्डी का जादू काम कर रहा है।

इस एग्जिट पोल में कुछ एजेंसियां उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में 70 तक सीटें दे रही हैं। यहां भी हम 2007 और 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल को याद कर सकते हैं। 2007 में ये पोल बसपा को बहुमत से दूर बता रहे थे पर पर 206 सीटों के साथ वह बहुमत में आ गयी थी। इसी तरह 2012 में भी पोल में किसी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया था जबकि 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। इसी तरह दिल्ली के चुनावों में कोई भी एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं दे रहा था जबकि उसका प्रदर्शन पोल के विपरीत बहुत अच्छा रहा और उसने सरकार तक बना ली। मतलब इन एग्जिट पोलों को एजेंसियों के मनमौजीपन के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। चुनाव परिणाम आने में चंद दिन ही शेष हैं, इसलिए सच जो कुछ भी होगा वह सामने आ ही जाएगा।

**केजरीवाल के सवाल 22-2-2014**

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल के लगातार मजबूती से उठाए जा रहे सवालों ने राहुल और मोदी के बीच बयानबाजी और शिगूफों तक सिमटी राजनीतिक को एक मुकम्मल शक्ल देनी शुरू कर दी है। यह देखना मजेदार है कि किस तरह एकदम नयी और

छोटी सी राजनीतिक जमीन पर खड़े होकर 'आप' नेता ने इन धुरंधरों की 'फेंकू' और 'पप्पू' टाइप बहस को बीच से लपक लिया है और देखा जा रहा है कि ये दोनों ही महारथी कुछ साफ-सुथरा जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। केजरीवाल के बीच में आ जाने से यह जरूर हुआ है कि राहुल गांधी को थोड़ी राहत मिल गयी है और अब मोदी का सीधा निशाना बनने से वे एक हद तक बच जाएंगे। केजरीवाल ने चिट्ठी लिख मोदी से पूछा है कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आएगी तो क्या वह स्विस बैंक में जमा काला धन वापस लाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंबानी बंधुओं का विदेशों में कालाधन है। उन्होंने दो अकाउंट नंबर ( 5090160983 और जिनेवा के एचएसबीसी बैंक का 5090160984) का भी चिट्ठी में जिक्र करते हुए दावा किया है कि ये खाते मुकेश और अनिल अंबानी के हैं, जिनमें उनकी काली कमाई रखी गई है।

केजरीवाल ने मोदी से उनकी रैलियों की बाबत भी पूछा है कि उसके लिए पैसे कहां से आते हैं? क्या वह खर्च मुकेश अंबानी उठाते हैं। पत्र में मोदी से गैस के दामों पर भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। अंबानी की कंपनी गुजरात में बड़े पैमाने पर गैस उत्पादन करती है। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली समेत अन्य पर गैस कीमतों में कथित अनियमितता बरतने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधी शाखा से एफआइआर दर्ज करने को कहा था। केजरीवाल ने मुकेश अंबानी से चुनावी फंड के रूप में एक पैसा भी नहीं लेने की बात भी कही है। जबकि इसी सप्ताह 'आप' नेता और उसके थिंक टैंक माने जाने वाले योगेन्द्र यादव ने अंबानी से चंदा लेने में परहेज नहीं है, ऐसा कहकर 'आप'की धार को कुंद कर डाला था। केजरीवाल का यह पलटवार योगेन्द्र के बयान के बाद 'आप' की हुई फजीहत से भी पार्टी को निकालने का एक प्रयास है। अगर मोदी और राहुल का मीडिया मैनेजमेंट मजबूत है और वे उस पर करोड़ों खर्च कर अपना चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं, तो केजरीवाल ने भी अपनी छोटी सी राजनीतिक अवधि में अपनी तरह से मीडिया को प्रभावित करने का तरीका विकसित किया है।

मोदी के कॉरपोरेट प्रचार तंत्र को चुनौती देते केजरीवाल ने कहा है कि अपनी चिट्ठी की 10 करोड़ प्रतियां छापकर देश की जनता के बीच में बांटेंगे। केजरीवाल ऐसी ही एक चिट्ठी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी लिखने वाले हैं। इस तरह अब तक दो सिरों पर लेने-देने का खेल खेलते मोदी और राहुल के बीच सिमटी बहसों को 'आप' जिस तरह से खोलने और जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है उससे लोकसभा चुनाव होने तक चुनावी फिजा के बदलने की संभावनाएं दिखती हैं। 'आप' के आने से बाकी राजनीतिक छोरों पर समेट दिए गए सपा, बसपा, तृणमूल आदि को भी अपनी-अपनी जमीन दिखने लगी है। इससे और चाहे जो भी हो, मोदी की दहाड़-पछाड़-जुगाड़ हवा होती जा रही है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक 'सकारात्मक'घटना है। केन्द्रीय सत्ता किसी व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षाओं और जिदों की मोहताज ना हो यह उसके जीवित रहने की पहली शर्त है।

**<u>मंडेला की वसीयत 5-2-14</u>**

हामानव नेल्सन मंडेला के जीवन की तरह उनकी वसीयत से भी उदारहृदयता का पता मिलता है। अपनी वसीयत में उन्होंने न केवल अपने परिजन को हिस्सेदारी दी है बल्कि अपनी पार्टी, अपने स्कूलों, जिनमें उन्होंने शिक्षा पायी और अपने सहायकों तक का ख्याल रखा है। कभी मंडेला ने कहा था- 'जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह निभाता है, तो उसे शांति मिलती है, मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है और इसलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूँ।' अपनी वसीयत से उन्होंने अपने कहे को साबित किया है।

पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों के लिए भी 50, 000 रैंड की राशि छोड़ी है। इनमें दो दशकों तक उनकी सहायिका के रूप में सेवा करने वाली जेल्डा लॉ ग्रेंज भी एक हैं। मरणोपरांत जेल्डा ने उनके बारे में जो कहा है वह मंडेला के अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार के बारे में भी बताता है। जेल्डा कहती हैं- मंडेला ने पिछले 19 वर्षों में मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, यह उनका आशीर्वाद था और मैं खुद को सम्मानित महसूस करती हूं। वे कहती हैं कि नेल्सन मंडेला ने कभी अपने प्रति वफादारी की मांग नहीं की थी , लेकिन उनका जीवन ही ऐसा है जिसने जिस किसी को छुआ उसे अटूट वफादारी को प्रेरित किया।

मंडेला की संपत्ति के निष्पादकों में से एक न्यायमूर्ति डिकजैंग मोसेन्के ने सोमवार को जोहांसबर्ग में नेल्सन मंडेला सेंटर में मंडेला की वसीयत को पढ़ा। वसीयत के अनुसार मंडेला के सभी नजदीकी निजी कर्मचारियों को 50,000 रैंड मिलेंगे। जिन स्कूलों में मंडेला पढ़े थे, उन्हें एक लाख रैंड दिए जाएंगे। इसके अलावा मंडेला ने वसीयत में चार अन्य शैक्षिक संस्थानों में छात्रवृत्ति के लिए एक लाख रैंड देने को कहा है। मंडेला का परिवार भी उनकी वसीयत से 'काफी खुश' था, जब वसीयत पढ़ी गई तब मंडेला परिवार भावनाओं से ओत-प्रोत हो गया था। वसीयत के अनुसार मंडेला के अपने परिवार के ट्रस्ट को 15 लाख रैंड और रॉयल्टी मिलेंगी। मंडेला ने अपनी पार्टी के लिए भी रॉयल्टी के कुछ हिस्से की व्यवस्था की है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी को मिले रॉयल्टी के हिस्से को पार्टी की कार्यकारी समिति अपने विवेक से, पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सकती है।

नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्लीय सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया था और इसके लिए वह 27 साल तक जेल में रहे थे। फरवरी 1990 में नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जेल से रिहा किया था और इसी साल हर तरह के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त करने वाले मंडेला को भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान भारत र}

से नवाजा था। इसके बाद 1993 में एफ डब्ल्यू डी क्लार्क के साथ उन्हें संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1994 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति का पद संभाला था। नवंबर, 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने मंडेला के जन्म दिवस 18 जुलाई को वर्ष 2010 से हर साल 'नेल्सन मंडेला दिवस' के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था।

अपने आरंभिक दिनों में ही मंडेला में एक क्रांतिकारी जीवन की जिद दिखने लगी थी जिससे चिंतित उनके परिवार ने उनका विवाह कराकर उन्हें जिम्मेदारियों में बांधने का प्रयास किया था, परन्तु निजी जीवन को दरकिनार करते हुए नेल्सन घर से भागकर जोहांसबर्ग चले गये और वहां उन्होंने सोने की खदान में चौकीदार की नौकरी की। एक चौकीदार के रूप में काम करने से लेकर लंबी जेलयात्रा और राष्ट्रनायक बनने से लेकर राष्ट्रपति पद तक जाने और नोबल और उसके बाद का उनका पूरा जीवन ही चरम संघर्ष और चरम उपलब्धियों की मिसाल सा है। इस बाजारवादी आत्मकेंद्रित होते चरित्रों से भरी दुनिया में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का जीवन चरित्र नैतिक मानक मूल्यों की ऐसी बानगी है, जो भविष्य के कठिन होते समय में दबे-कुचले व्यक्ति को उठ खड़े होने और फलक छू लेने को प्रेरित करती रहेगी।

इस बाजारवादी आत्मकेंद्रित होते चरित्रों से भरी दुनिया में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का जीवन चरित्र नैतिक मानक मूल्यों की ऐसी बानगी है, जो भविष्य के कठिन होते समय में दबे-कुचले व्यक्ति को उठ खड़े होने और फलक छू लेने को प्रेरित करती रहेगी।

**ग्लैमर और प्रियंका 17-1-14**

भाजपा नेत्री और गांधी परिवार की बागी बहू मेनका गांधी ने अपनी भतीजी प्रियंका गांधी के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर वार किया है। मेनका ने कहा है कि कांग्रेस को अब प्रियंका का ग्लैमर या क्रेज भी नहीं बचा सकता। मेनका यह भी मानती हैं कि लोकसभा चुनावों में भाजपा का कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वैसे, लोकसभा चुनावों में क्या होता है, ये तो परिणाम ही बताएंगे और यह अनुमान भी है कि कांग्रेस इस बार नुकसान में रहेगी। कांग्रेस का क्या हाल होना है, विधानसभा चुनाव इसका आभास दे चुके हैं लेकिन मेनका के बयान में प्रियंका को खास तौर पर इंगित किया जाना, कहीं न कहीं कांग्रेस के विरोधियों में किंचित् घबराहट का संकेत भी देता है। अगर हम बार-बार कहें कि हम किसी चीज से डर नहीं रहे हैं, तो परोक्ष रूप से यह उसके प्रति भय के कारण भी होता है। यह सच्चाई है कि बुरे परिणामों से आशंकित कांग्रेस के तरकश में प्रियंका एक ऐसा तीर हैं, जिसे अभी चलाया नहीं गया है। पिछले कई चुनावों में प्रियंका की सक्रियता को लेकर बयान आते रहे हैं। वे कुछ दिनों तक लोगों से मिलती- जुलती दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। भाजपा खेमे में इस बात को लेकर थोड़ी घबराहट हो सकती है कि अगर प्रियंका सक्रिय राजनीति में उतरती हैं, तो वह लोगों और मीडिया का ध्यान आकृष्ट कर सकती हैं।

प्रियंका को लेकर कांग्रेस की उम्मीदों और भाजपा की घबराहट की वजहें भी हैं। खुद मेनका ने ही इसका जिक्र भी कर दिया है। वे इसे ग्लैमर या क्रेज का नाम देती हैं। अगर यह कहें कि दिवंगत संजय और राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार में सोनिया, मेनका, राहुल या वरुण का वैसा ग्लैमर या क्रेज नहीं है, जो प्रियंका का है तो यह गलत भी नहीं होगा। कुछ लोग उन्हें उनकी दादी इन्दिरा गांधी से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए मेनका गांधी सोनिया या राहुल का इस रूप में जिक्र नहीं करतीं जिस प्रकार प्रियंका का करती हैं। ग्लैमर या क्रेज ने लोकतंत्र का नुकसान ही किया है, यह मानते हुए भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसका प्रभाव होता है। राजनीतिक दलों ने इसी कारण हमेशा से फिल्म कलाकारों या क्रिकेट जैसे दूसरे क्षेत्र के लोगों को राजनीति के मैदान में उतारा है। चाहे प्रत्याशी के रूप में हो या फिर प्रचार के लिए, फिल्मी कलाकार या क्रिकेट खिलाड़ी अक्सर अपने ग्लैमर का लाभ पाते हैं। सपा ने तो इस बार कामेडियन राजू श्रीवास्तव को भी टिकट दिया है। अपवादों को छोड़ दें तो ऐसे ज्यादातर मामलों में मतदाताओं को बाद में निराशा ही मिलती है।

अपने फायदे लेकर वे फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और जनता को उनकी समस्याओं के साथ छोड़ देते हैं।

वास्तव में यह राजनीति की उसी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां हम दल की नीतियों, घोषणाओं और इतिहास को भूलकर व्यक्ति को मुख्य मान लेते हैं। जब ग्लैमर या क्रेज होता है, तो सिर्फ उसकी चकाचौंध होती है, लेकिन यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि कई बार ऐसा भी हुआ है, जब यह चकाचौंध मतदाताओं की दृष्टि धुंधली नहीं कर सकी है। सभाओं में भीड़ जुटाना एक बात होती है और उसे वोट में बदल पाना दूसरी बात। अगर प्रियंका गांधी के साथ ग्लैमर और क्रेज है, जिसका जिक्र कांग्रेस में अक्सर होता है और मेनका गांधी भी जिसकी ओर इशारा कर रही हैं, तो इसे निकष पर कसने की भी जरूरत है।

**तीन सौ रामायणों 12-1-14**

संजीव कुमार द्वारा संपादित राजकमल प्रकाशन से आयी पुस्तक तीन सौ रामायणों एवं अन्य निबंध अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कन्नड़ और अंग्रेजी के रचनाकार ए.के.रामानुजन के आलेख तीन सौ रामायणों पांच उदाहरण और अनुवाद पर तीन विचार पर हुए विवाद के संदर्भ में विमर्श के रूप में सामने

आए आलेखों का संकलन है। 2012 में हिन्दुत्ववादियों का निशाना बनकर यह लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पाठ्यक्रम से निकाला जा चुका था। इस आलेख में रामायण के दुनिया भर में उपलब्ध पाठांतर, रूपांतर और वाचन पर तुलनात्मक आधार पर विचार किया गया है। जैसा कि आम तौर पर माना जाता है कि सारी रामायणों वाल्मीकि के आख्यान को ही अपनी भाषाओं में ले जाने का काम नहीं करतीं और वाल्मीकि, कम्बन या कृतिवास के पाठों में फर्क है। कथा सामान होने पर भी उनका विमर्श बहुत भिन्न है। ये रचनाकार वाल्मीकि की सामग्री का इस्तेमाल तो करते हैं पर उसमें वे अपनी क्षेत्रीय लोकपरंपराओं को भी शामिल कर लेते हैं। वाल्मीकि और कम्बन की रामायण पर विचार करते रामानुजन पाते हैं कि कम्बन के यहां नाटकीयता ज्यादा है। जहां कम्बन के राम शत्रुहंता और तमिल नायक हैं वहीं वाल्मीकि के राम ईश-मानव हैं और मनवीय रूप की सीमाओं में रहते हैं। कुछ विद्वान की नजर में वाल्मीकि के यहां राम को अवतारी बनाने वाले कांड बाद के प्रक्षिप्त अंश हैं। रामानुजन पाते हैं कि तुलसी के रामचरितमानस और मलेशियाई हिकयत सेरी राम में कुछ ब्योरे कम्बन की रामायण पर आधारित हैं।

रामायण के जैन वाचन में रावण को खलनायक बनाने के लिए ब्रा◌ाणों को जिम्मेदार माना गया है। रावण जैन परंपरा के तिरसठ शलाका पुरुषों में एक हैं और जैन कवि विमल सूरि राम की नहीं, रावण की महानता के बखान से कथा की शुरुआत करते हैं। जैन वाचन में राम रावण का वध नहीं करते क्यों कि वे एक उन्नत आत्मा हैं, वहां रावण का वध लक्ष्मण करते हैं और नरक जाते हैं। दक्षिण भारतीय लोक आख्यानों में राम कथा अलग ही रूप में है। कन्नड़ में सीता का मतलब उसने छींका है, वहां सीता रावण की छींक से पैदा हुई मानी जाती है। वहां रावण के गर्भ से पुत्री के रूप में सीता की जन्म की भी एक जुदा कथा है। कहीं-कहीं कथा है कि रावण की लोलुपता का शिकार सीता उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसका नाश करती है।

रामानुजन के अनुसार तिब्बत,थाइलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, जावा और इंडोनेशिया में रामकथा के अलग अलग वाचन मिलते हैं। थाई रामकहानी रामकियेन में सीता के द्वारा बनाई गई रावण की तस्वीर देख राम ईर्ष्या के आवेग में सीता को मार डालने का आदेश देते हैं पर सदय लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ आते हैं और मार डालने के सबूत के तौर पर एक हिरण का ह्रदय लेकर लौटते हैं। थाई कहानी में सीता हरण रावण का प्रेमवश किया गया कार्य है, थाई लोगों को रावण द्वारा एक स्त्री के लिए अपने राज और जीवन का बलिदान मार्मिक लगता है। रामानुजन दिखलाते हैं कि जहां वाल्मीकि राम को केंद्र बनाते हैं वहीं विमल सूरी की और थाई रामायण रावण को केंद्रीय चरित्र बनाते हैं और अद्भुत रामायण और तमिल शतकंठवन में सीता मुख्य चरित्र हैं। इस तरह रामकथा जड़ नहीं है एक जीवंत कथा है जिसमें अन्य क्षेत्रिय स्थितियों के हिसाब से कथा के पाठ कई तरह से प्रस्तुत होते हैं।

पुस्तक में संकलित मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, रोमिला थापर, कामिल बुल्के आदि के आलेख भी रामानुजन की स्थापनाओं को तार्किक साबित करते हैं। आम जन में अपने ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर एक विाषणपरक दृष्टि विकसित करने में यह पुस्तक मददगार साबित हो सकती है।

**<u>अनसोशल होता मीडिया 6-6-14</u>**

विष्य में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के लिहाज से तकनीक के क्रांतिकारी पहलू के रूप में अब तक प्रचारित होता रहा सोशल मीडिया क्या अब आम लोगों के बीच विवाद पैदा करने और हिंसा को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में तो सीमित होकर नहीं रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते पुणो में सोमवार को महाराष्ट्र सोलापुर के निवासी शेख मोहसिन नामक आइटी इंजीनियर की हत्या की गयी उससे तो यही जाहिर हो रहा है। पुलिस को शक है कि इंजीनियर की हत्या फेसबुक विवाद के चलते की गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ज्यादातर हमलावर कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े हुए हैं।

पिछले आम चुनावों के समय जो भय नरेन्द्र मोदी सरकार के आगमन की आशंका के रूप में प्रचारित किया जा रहा था और आम सभाओं में जिसका निवारण करने को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार सकारात्मक घोषणाएं भी की थीं, आज की तारीख में ऐसी घटनाएं उस भय को पुन: तेजी से जमीन मुहैया कराती दिख रही हैं। इस प्रकरण पर पुणो से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण शिरोले ने जिस तरह से कहा है, कि आप लोग जितना इस मामले को बड़ा कर रहे हैं, उतना यह है नहीं, वह और चिंता पैदा करने वाला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने हमले के पीछे राष्ट्रवादी हिंदू सेना का हाथ होने से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ लोग शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोहसिन के परिवार से मिलने तक की जरूरत महसूस नहीं की। इससे तो यही बात स्थापित होगी कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छे दिनों का नारा हर भारतीय के लिए नहीं है। क्या यह अच्छे दिन केवल हिंदू राष्ट्रसेना के कार्यकर्ताओं के लिए आए हैं, इसका जवाब तो देना होगा। मोहसिन पर हमले के वक्त वहां मौजूद उसके दोस्त रियाज ने द हिंदू अखबार को बताया, 'मैं इसलिए बच गया क्योंकि मुङो दाढ़ी नहीं थी। मैंने टोपी नहीं पहन रखी थी। मोहसिन इसलिए मारा गया क्योंकि वह मुसलमान की तरह लग रहा था।' हमलावर इससे पहले भी दो युवकों को अपना निशाना बना चुके हैं। फेसबुक विवाद के चलते पुणो में अब तक कई जगह हिंसा की वारदात हो चुकी है। मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस बीते एक हफ्ते में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूं सादिक की मौत और फेसबुक तस्वीरों के बीच सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि 'फेसबुक पर आपत्तिजनक तस्वीरें किसी न किसी तरह सादिक की मौत की जिम्मेदार बनीं।' तो क्या सोशल साइट्स अब ऐसी ही कारस्तानियों का मंच बनकर रह जाने वाला है, इस पर विचार करना होगा क्योंकि

इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। लोगों की दूसरों के बारे में जानने की लालसा और बाजारवाद के इस दौर में खुलेपन की कीमत बहुत बड़ी साबित हुई है। इसलिए फेसबुक पर डाली गई किस तस्वीर के कारण कहां कौन अकारण ही ऐसी बेरहमी से मार दिया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता।

**खींचतान में गांधी-नेहरू 18-11-14**

भारत की आजादी के आंदोलन के कर्णधारों और राष्ट्र निर्माताओं महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल की विरासत को लेकर लंबे समय तक भारत का शासक दल रही कांग्रेस और सत्तासीन भाजपा के बीच जिस तरह की मारा-मारी मची है, वह एक ओर जहां इन महानायकों की भारतीय जन में स्थिति और उनकी वैचारिक ताकत के बारे में बतलाती है, वहीं इस तरह की तुच्छ छीना-झपटी में लगे इन दोनों दलों के नायकों के बचकानेपन को भी उजागर करती है। यह इन महान व्यक्तित्वों की जादूगरी ही है कि विकास के आधुनिक नारे और संघ के समर्थन के साथ सत्ता में आई भाजपा के शीर्ष व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लगातार गांधी और नेहरू के मुरीद होते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस इन व्यक्तित्वों की विरासत को अपनी थाती समझने की भूल कर रही है। यह जादू ही है कि गांधी और नेहरू को लेकर आजादी के बाद से ही विषवमन करने वाला संघ मोदी की इस नवधा गांधी भक्ति को लेकर शांत है। अब मोदी का नया दावा है कि वे प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही गांधी के विचारों के कायल रहे हैं। हालांकि, इस सबसे गांधी-नेहरूका कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं, पर इस तरह अगर मोदी जनमत को अपने अनुकूल करने में कामयाब होते दिख रहे हैं, तो इस पर हाय तौबा मचाकर कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। आखिर अपने लंबे शासनकाल में कांग्रेस ने गांधी-नेहरू के सपनों को बेचने के सिवा उसे अमल में लाने के लिए किया ही क्या है?

नेहरू की 125 वीं जयंती पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नेहरू की विरासत को दृढ़तापूर्वक सामने रखने का प्रयास करते हुए और भाजपा पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनके (नेहरू के) विचारों पर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि तथ्यों को गलत ढंग से रखा जा रहा है और तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कि धर्मनिरपेक्षता के बिना कोई भारतीयता नहीं हो सकती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह एक अकाट्य जरूरत है। लोकसभा चुनावों में करारी हार के छह महीने बाद कांग्रेस द्वारा आयोजित अपनी तरह के इस पहले वैश्विक आयोजन में व्यक्त सोनिया गांधी के इन विचारों के पीछे की तड़प को समझा जा सकता है। इसे कांग्रेस की सभी गैर भाजपा और गैर राजग दलों को धर्मनिरपेक्षता की छतरी तले एकजुट करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। परमाणु करार के मुद्दे को लेकर वाम दलों ने 2008 में संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 2012 में संप्रग सरकार से नाता तोड़ा था। पर, इस सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, जनता दल (सेक्युलर) के एच डी देवगौड़ा, जनता दल (यू) के शरद यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डी पी त्रिपाठी आदि तमाम लोगों ने हिस्सा लिया।

इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं करना कांग्रेस के भय को ही उजागर करता है। अगर मोदी संघ के प्रतीकों की जगह गांधी-नेहरूको अपने वैचारिक आधार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे डरने की क्या जरूरत है। सकारात्मक विचार किसी दल या व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होते। भारत के हर नागरिक को उन पर अमल की स्वतंत्रता है और इसे लेकर कांग्रेस को ऐसी उलटबांसियों से उबरना चाहिए कि यह मेरा है और वह तेरा है, वह उनका है जो उस पर अमल करना चाहते हैं।

**तांत्रिक कसाईबाड़ा 17-11-14**

क्कीसवीं सदी में एक ओर जहां 'शाइनिंग इंडिया' के बाद अब 'मेक इन इंडिया' के नारों के साथ हम विश्वविजयी मुद्रा में दुनिया भर में कुलांचे मारते अपनी गाथा का गान करते घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश भारत में अभी भी बच्चों की बलि की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मोदी मंत्र का लोहा मानती दुनिया की खबरों पर लहालोट होते हम अपनी दुनिया के अंधेरों में तंत्र-मंत्र का शिकार होते मासूमों की ली जाती जान को कभी भी राष्ट्रीय बहस के केंद्र में नहीं ला पाते ना शिशुबलियों को प्रेरित करने वाले तांत्रिक के गर्हित कर्म को अवैध घोषित करने की मांग कर पाते हैं। आखिर यह कैसा विकास है जिसकी चौंधियाती रोशनी में अपने ही बाल-गोपालों की चीखों को हम अनसुना करते हुए जीते चले जाने को मजबूर हैं। कासगंज जिले के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर में विगत शनिवार की सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जब एक पिता ने अपने ही तीन महीने के मासूम बेटे की बलि देकर खून से सने हाथों से मंदिर में दुर्गा और शंकर की मूर्तियों का तिलक किया। आखिर यह कौन सा नशा था जो विनीत को सत्य और सुंदर के देवता शिव को बलि चढ़ाने को अंधा कर रहा था। सवाल उठता है कि ऐसे गर्हित नशे के मरीजों की पहुंच हमारे पवित्रता के केंद्र माने जाने वाले मंदिरों तक कैसे हो जाती है और इसे रोकने के उपाय कौन करेगा?

बच्चों की बलि की ऐसी घटनाएं तमाम प्रांतों से आती रहती हैं। पिछले महीने सुल्तानपुर में संतान की लालच में बच्चे की बलि देने वाले तांत्रिक व पिता-पुत्र को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी तरह असम में एक व्यक्ति ने अपने 13 वर्षीय बेटे, प}ी और दस वर्षीय बेटी की बलि इसलिए दे दी थी, क्योंकि उसके सपने में 'प्रकट' होकर देवी ने बलि की मांग की थी। तीन साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक तांत्रिक की सलाह पर महिला ने

अपने सौतेले बच्चे की बलि दे दी थी। इसी साल मार्च में रायपुर में दो साल के मासूम की बलि देने के आरोप में भिलाई के एक तांत्रिक, उसकी प}ी और उसके पांच चेलों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर में एक पिता ने अपने 13 माह के बेटे की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी, पर पुजारी की पहल पर उसे रोका जा सका था। इसी तरह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जिले हिंगोली में चार साल पहले दो महीने में पांच नरबलि दिए जाने का मामला सामने आया था। छठे बच्चे की बलि देने से पहले हत्यारे पकड़ लिए गए थे। तांत्रिक ने बच्चे की चाहत वाले उस दंपति को 11 बच्चों की बलि की सलाह दी थी। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि धार्मिक अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा हमारे समाज का ही एक हिस्सा किस तरह 'कसाईबाड़े' में बदलता जा रहा है। अंधविश्वास की छुरी आखिर कब तक इनसानियत को काटती रहेगी? अगर इसे रोकने की पहल नहीं की गई तो संतुलित विकास की कोई मिसाल आखिर हम कैसे दे पाएंगे?

**राम बनाम शिवाजी 11-11-14**

लोकसभा चुनावों के समय सीटों के बंटवारे के मुद्दे, विधानसभा चुनावों में किसका मुख्यमंत्री हो तथा अन्य मुद्दों पर जो दशकों से चला आ रहा गठजोड़ टूटा और हिन्दूवादी पार्टी भाजपा और शिवसेना के बीच दरार जिस तरह से पड़ी उसकी फांक धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है। वह हिंदूवादी राजनीति की सीमाओं, उसके अंतर्विरोधों और विडंबनाओं की ओर ही इशारा करती है। महाराष्ट्र विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के पहले ही दिन शिवसेना और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए। जहां शिवसेना विधायकों ने शिवाजी के नारे लगाये, वहीं भाजपा विधायकों ने जय र्शीराम के नारे लगाए। शिवसेना विधायक विपक्ष की सीट पर जाकर बैठ गए। इसके साथ ही फड़नवीस सरकार के मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के फैसले पर भी शिवसेना के सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया। देखा जाए तो स्थानीय और अखिल भारतीय का यह अंतर हिंदूवादी राजनीति की मुख्य सीमा है, यह भारत में धर्म की राजनीति की भी सीमा है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से जब इस सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं अपना हल खुद ढूंढ लेती हैं। यहां देखा जा सकता है कि कल तक किसी भी मुद्दे का हल साझे तौर पर ढूंढने वाले दल आज किस तरह इसको समय की दया पर छोड़ रहे हैं।

जिस तरह की कटुता भाजपा शिवसेना के बीच बढ़ी है उसने उन्हें जोड़ने वाली हिन्दू आस्था की जडें़ हिला दी हैं। आस्था से कभी दूर तक राजनीति नहीं की जा सकती। वह तुरंत ही भावना पर चोट का कारक बनती है। देश के बड़े भू-भाग में रहने वाले हिन्दुओं की आस्था के स्रोत एक नहीं हैं और आस्थाएं अलग-अलग कारणों से कब कैसे चोटिल हो जाएंगी, कुछ किया नहीं जा सकता। यही वैचारिक बाधा आज भाजपा शिवसेना को लगातार एक दूसरे से दूर कर रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का कहना है कि हमने भाजपा को सर्मथन इसलिए दिया है ताकि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार रहे। दूसरी ओर एनसीपी के सहयोग पर शिवसेना का विरोध स्पष्ट है कि जिसका विरोध कर भाजपा सत्ता में आई है उसका साथ कैसे लिया जा सकता है? देखा जाए तो केंद्र में अकेले दम पर सत्ता में आने के बाद अब भाजपा कहीं किसी के दबाव में रहकर राजनीति नहीं करना चाहती, ऐसे में शिवसेना के लगातार हमलावर रुख से भाजपा उसके साथ खुद को सहज नहीं कर पा रही।

शिवसेना ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया था कि वह अपना रुख साफ करे कि वह उसे सरकार में सहयोगी बनाना चाहती है या नहीं। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह उपमुख्यमंत्री पद को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा शिवसेना ने 14 मंत्री पद मांगे, भाजपा नहीं मानी तो 12 फिर 10 और आखिरकार 8 कर दी। लेकिन इस सूरत में वह गृह विभाग जैसे किसी बड़े मंत्रालय के लिए दबाव बना रही थी। भाजपा इस पर तैयार नहीं थी। इसके मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने भाजपा को अपनी शर्तें मानने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया, नहीं तो वह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए शिवसेना ने भाजपा को तीन-चार दिनों की मोहलत दी थी, जिसे भाजपा ने खारिज कर दिया। भाजपा और शिवसेना में मतभेद तो पहले भी थे, लेकिन अब मनभेद भी होता जा रहा है। अगर भाजपा के सत्तासीन होने के बाद के मानस को शिवसेना नहीं समझती तो वह बनी रहे महाराष्ट्र में हिंदू ह्रदय सम्राट। भारत के सम्राट मोदी उसकी क्योंकर सुनेंगे।

**जेठमलानी और 370 ,10-11-14**

रिष्ठ वकील और भाजपा नेता राम जेठमलानी ने 370 को मजबूती देने वाला बयान देकर सबको चौंका दिया है। संभव है यह बयान कश्मीर चुनावों के मद्देनजर मोदी की तरफ से दिलाया गया हो वरना कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद का कट्टर विरोध करने वाली पार्टी का नेता ऐसा बयान क्यों देता? जम्मू-कश्मीर को एक भिन्न व विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को लेकर हमेशा से एक बहस रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी धारा 370 को एक 'अस्थायी प्रबंध' बताया था और 27 नवम्बर 1963 को लोकसभा में कहा था कि इसको खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पर नेहरू की मौत के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने चार दिसंबर 1964 को लोकसभा में कहा कि 370 को रखें या हटा दें, यह अपना असर दिखा चुकी है। सरदार पटेल और नेहरू में भी इस धारा की वजह से खटास आ गई थी। लेकिन जब नेहरू विदेश यात्रा पर थे तो पटेल ने ही एन. गोपालस्वामी अयंगर के कहने पर इसे पास करा डाला था। संविधान निर्माता अम्बेडकर भी इसे भारत की स्थिरता के लिए खतरनाक मानते थे और कश्मीरी चिंतक और कवि मौलाना हसरत मोहानी तक इसके खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्तासीन होने और

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही पीएमओ में नियुक्त राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने संबंधी बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अप्रत्यक्ष तौर पर नेहरू को सारे फसाद की वजह बताते हुए कहा था कि पटेल होते तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा निबटा दिया होता। शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी 370 हटाने को लेकर बयानबाजी से आगे जाकर कोई सार्थक कदम उठाने की मांग की थी।

भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चुनावी रैलियों में ही साफ कर दिया था कि भाजपा सत्ता में आती है, तो जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच दशकों से लागू धारा 370 को हटा दिया जाएगा। राजनाथ के अनुसार धारा 370 के लागू होने से कश्मीर के निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला है बल्कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने '44 प्लस' सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, पार्टी ने धारा 370 से ज्यादा विकास और दो परिवारों, अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कांफ्रेंस और मुफ्ती परिवार की पीडीपी, के कथित कुशासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया है। दरअसल भाजपा को फिलहाल चुनाव जीतना है और जिस तरह लोकसभा चुनावों के समय जीत के लिए भाजपा ने अपने पुराने मंदिर के मुद्दे को किनारे कर दिया था और विकास और परिवारवाद से मुक्ति के नाम पर चुनाव जीता था, अब जम्मू-कश्मीर में भी जीत के लिए वह इन्हीं मुद्दों पर जोर देना चाहती है। देखना है जनता उसके इन शिगूफों को कितनी गंभीरता से लेती है।

**<u>विकल्प को महामोर्चा 7-11-14</u>**

माजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की अगुआई में बिखरे हुए पुराने जनता परिवार के एका की कोशिशें इस बार रंग लाती दिख रही हैं। केंद्र में पहली बार अपने बूते सरकार बना पाई भाजपा को एकजुट होकर चुनौती देने के इरादे से सपा, जद(यू)और राजद ने एक बार फिर महामोर्चा बनाया है। यह महामोर्चा भविष्य में भाजपा को घेरने और पराजित करने की रणनीति के तहत बनाया गया है। यह मोर्चा जहां एक ओर कांग्रेस को निशाने पर नहीं लेगा वहीं दूसरी ओर वामदलों की सहानुभूति भी इनके साथ रहेगी। देखा जाए तो यह विगत लोकसभा चुनावों में पराजित दलों द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बनाया गया संगठन है। इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि यह अपने निजी हितों को किनारे कर आमजन के हित में विकास, रोजगार आदि के मुद्दे पर कैसे और कहां तक एका बनाए रख पाते हैं? इनके एक होने से सत्ता के समीकरणों में अंतर पड़ेगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में लालू और नीतीश के एका का असर पड़ा भी, पर यह सबकुछ किसी बड़े फेरबदल को तब तक संभव नहीं कर पाएंगे जब तक ये दल अपने अंतर्निहित अहम को नियंत्रित कर लोकतंत्र के चरित्र के अनुकूल परिवारवाद आदि से निजात नहीं पाएंगे। परिवारवाद के आधार पर मोदी के हमलों का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिन मुलायम सिंह यादव के घर इस महामोर्चा की बैठक हुई है देखा जाए तो पार्टी के नाम पर संसद में उनका परिवार ही काबिज है। देवेगौड़ा की भी यही हालत है। इन्हें अपने परिवार से बाहर जाकर जन विकल्पों की तलाश करनी होगी वरना इस तरह की कसरत अलहदा परिणाम सामने नहीं ला पाएगी। कांग्रेस में चुनावी हार के बाद परिवार के साये से मुक्ति के स्वर कहीं से उठते भी हैं तो उसे आधार नहीं मिलता, पर इस सबसे मुक्ति पाए बिना भारतीय लोकतंत्र में इन स्वकेंद्रित दलों को अपने लिए नई जमीन तलाश पाना कठिन होगा।

इस महामोर्चा की बैठक में नीतीश कुमार ने आशा जताई है कि उनकी यह कवायद भविष्य में एक पार्टी के रूप में सबको संगठित करने की ओर जा सकती है। बैठक में लालू प्रसाद यादव ने भी अतीत में तीसरे मोर्चे से खुद को बाहर रखने को अपना गलत निर्णय बताया है। एक जुट हो रहे इन तमाम दलों में काला धन, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में एकजुट होकर सशक्त विपक्ष के रूप में लड़ने पर सहमति बनी है। नीतीश ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले धन पर बड़ी-बड़ी बातें कही गई थीं, अब मुंह मोड़ा जा रहा है। इसी तरह युवाओं को रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे और अब नियुक्ति पर एक साल की रोक लगाने की बात की जा रही है। इस बैठक में नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद, देवगौड़ा और दुष्यंत चौटाला आदि नेता शामिल हुए।

लोकतंत्र एक तरह से विकल्पों का भी तंत्र है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में किसी एक विचार से दूर तक जनता को हांक पाना संभव नहीं है। व्यापक जनहित में लगातार उद्यम से ही मोदी केंद्रित वर्तमान सत्ता से लोहा लिया जा सकता है। यह कोई कठिन चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा भी एक मात्र मोदी मंत्र के भरोसे चल रही है जो कि एक सहज लोकतांत्रिक मुद्रा नहीं है पर इसे चुनौती देने के लिए परिवारवाद और निजी अहम के 'राक्षसों' से निपटना इन क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी।

**<u>चांद-मंगल व विकास 6-11-14</u>**

लिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा 'मौजूदा पर्यावरण और वायु प्रदूषण का भारतीय कृषि पर प्रभाव' शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित आलेख भारतीय जनजीवन के भविष्य को लेकर खतरे की घंटी की तरह है। विकास के तमाम दावों और तरह-तरह की हाइटेक कसरतों के बाद भी भारत अभी गांवों का देश है और किसानी और खेती अभी भी हमारी रीढ़ है। विकास के कितने भी नए मील छू लेने के बावजूद यह संभव नहीं कि हम खेती आदि को नकार कर पश्चिम के कुछ देशों की तरह केवल तकनीकी विकास को आधार बनाकर जीवित रह सकें। शोध के अनुसार वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर भारत के खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में बढ़ते प्रदूषित काले कोहरे के कारण फसलों की संभावित उपज आधी रह गई

है। परिणाम स्वरूप 2010 में जितनी फसल संभावित थी, उसके मुकाबले वायु प्रदूषण के कारण सघन राज्यों में गेहूं की उपज 50 फीसद तक कम हो गई है। वहीं, आवश्यक खाद्य सामग्री के उत्पादन में 90 फीसद तक की कमी आई है। काले कार्बन और अन्य प्रदूषक तत्वों से बना काला कोहरा तेजी से देश की मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट कर रहा है। इसके साथ ही वैश्विक तापमान बढ़ने से मौसम में होने वाले बदलावों के चलते भी खाद्यान्न की उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शोधकर्ताओं ने इस संबंध में सरकार को जो सुझाव दिए हैं, उन पर ध्यान दें तो यह साफ हो जाता है कि इस विकराल होती समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उठाने की जरूरत है। इससे लोग सहज तौर पर ऐसी जटिल समस्याओं के कारकों को समझ कर बड़े पैमाने पर उससे निपटने की ना केवल चेतना विकसित कर सकेंगे बल्कि उसे सफलतापूर्वक लागू भी कर सकेंगे। आधुनिक तथाकथित विकास की पोल यही है कि जहां सूचना के प्रसारण की तो गांव-घर तक व्यवस्था हो गई है, कल को हर हाथ में मोबाइल संभव है, पर उनका हम मनोरंजन आदि के अलावा कोई सार्थक उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि चेतना के स्तर पर हमें अपने परिवेश के खतरों की न केवल जानकारी हो बल्कि उन खतरों के मौलिक कारकों को हम अपने क्षेत्रीय संदभरें में पहचान कर उन्हें दूर करने में भी सफल हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतया हम पाते हैं कि लोग फसलों के कटान के बाद बचे डंठल और पशुओं के गोबर आदि का इस्तेमाल केवल जलावन के रूप में करना जानते हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि भारत सरकार को ऐसे जलावन के विकल्प के रूप में खाना बनाने के अन्य साधन व ईंधन मुहैया कराने चाहिए ताकि उत्पन्न वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। देश भर में दौड़ते ट्रकों के लिए बेहतर किस्म के फिल्टर्ड डीजल की व्यवस्था के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

प्रमुख शोधकर्ता जेनिफर बर्नी का कहना है कि सरकारें जब वायु प्रदूषण को दूर करने के उपायों के खर्च और नए कानूनों को बनाने पर चर्चा करती हैं तो वह उस समय कृषि को अपने जहन में नहीं रखतीं। पर, इन शोधों के आलोक में सरकार को वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों के प्रति सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने पिछले तीस साल के आंकड़ों का विषण करते हुए भारत का यह सांख्यिकीय मॉडल तैयार किया है। हमारे नीति वेत्ताओं को भी अपने देश के वैज्ञानिकों को ऐसे शोधों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए, तभी हम चांद-मंगल की यात्राओं और जमीनी विकास का संतुलन बना सकेंगे।

**<u>जिन्दगी रेस नहीं 3-11-14</u>**

डिया में अपनी आलोचना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एकबारगी कहा था कि जब लोग आपके बारे में अच्छा लिखते हैं, तो आप खुद को दुनिया में सबसे ऊपर समझने लगते हैं। जब लोग बुरी बातें लिखते हैं, तो आप खुद में सुधार करने की कोशिश करते हैं। पर, वाड्रा के इस पूर्व वक्तव्य की सच्चाई तब सामने आ गई, जब एक मीडियाकर्मी द्वारा उनसे जुड़े चर्चित जमीन सौदे को लेकर सवाल पूछे जाने पर वे आपा खोकर ना केवल असहज हो गए बल्कि उसकी माइक भी झटक दी। ऐसा करते समय वाड्रा भूल गए कि इंदिरा-राहुल गांधी के परिवार से जुड़ने के बाद वे केवल एक बिजनेस मैन नहीं रह गए हैं बल्कि एक लंबी राजनीतिक विरासत संभालने वाले नेहरू-गांधी परिवार के हिस्से हो चुके हैं। खासकर जब उन पर लगे आरोप लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रहे हों और उससे भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला हो, तब अपने व्यवहार में संयम की अपेक्षा तो उनसे की ही जाती है।

वाड्रा जितने बिजनेस मैन हैं, उससे ज्यादा चर्चा अपने जिम और कसरती शरीर को लेकर पाते रहे हैं। उनके कसरती शरीर की तुलना मीडिया में शाहरूख-सलमान की सिक्स एब्स पैक बॉडी से की जाती रही है। पर, ऐसा क्या कि आप सचमुच के जीवन में फिल्मी हीरोज की तरह गुस्सा दिखलाने लगें। कोई लोकतंत्र सार्वजनिक मंचों पर ऐसी अभिव्यक्तियों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वाड्रा फैशन और कार रेस के प्रति लगाव के लिए भी जाने जाते हैं, पर क्या उनके फैशन की सीमा कपड़ों तक सीमित है? बातचीत में उनका फैशन क्या उनकी इस शैली को जगह देता है? यूं देखें तो असहनशीलता और उतावलापन आज की युवा पीढ़ी में एक चिंतनीय बुराई की तरह पांव पसार रही है, पर वाड्रा जैसों को भी इसका ख्याल ना रहे तो जनता उन्हें कैसे माफ करेगी। अपने इस व्यवहार के बाद वाड्रा ने बिगड़ी हुई बात को सुधारने की कोशिश करते हुए कहा कि वे एक निजी कार्यक्रम में गए थे। उन्हें लगा कि कोई निजी फोटोग्राफर उनसे इस तरह के सवाल पूछ रहा है। उन्हें नहीं पता था कि सवाल पूछने वाला शख्स एएनआइ का रिपोर्टर है। यहां प्रश्न है कि सवाल पूछने वाला कोई भी हो, वह सड़क का एक साधारण सा आदमी भी हो सकता है इस लोकतंत्र में, इससे ऐसे उत्तेजनापूर्ण व्यवहार की इजाजत आपका जमीर कैसे दे सकता है। अब लोग सोशल मीडिया पर समुदाय बनाकर लिख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चोर है और उसे लाइक मिल रहे हैं। कांग्रेस ने भी खुद को इस प्रकरण से अलग कर लिया है। जिन्दगी फार्मूला वन कार रेस नहीं है, यह सीख तो अब तक वाड्रा को मिल ही चुकी होगी। अब चीजें राजनीतिक दबावों में एक शक्ल लेती जाएंगी। पर, सवाल है कि जमीन की डील का सच क्या उजागर हो पाएगा या काला धन के मामले की तरह राजनीतिक रोटियां सेंकने की जमीन बन कर रह जाएगा।

**<u>सपा का धनतेरस 23-10-14</u>**

त्तर प्रदेश सरकार ने धनतेरस पर राज्यकर्मियों के लिए दिवाली के उपहारों की घोषणाएं कर जनता में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार

करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार के बाद सपा सरकार अपने भविष्य को लेकर दबाव में चल रही थी। पर उसके बाद हुए उपचुनावों में भाजपा को प्रदेश में पछाड़कर सपा ने अपना आत्मबल फिर से बनाने की कोशिश की है। ऐसे कठिन समय में जब केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में पहली बार अपने बूते बहुमत की ओर बढ़त कायम की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की सीट छीनकर सपा ने खुद को और अपने सर्मथकों को आश्वस्त किया है। अब दीपावली पर राज्यकर्मियों को उपहार आदि भेंटकर राज्य सरकार धीरे-धीरे कायम हो रहे उत्साह को एक आधार देने की कोशिश कर रही है। खुशखबरी का पिटारा खोलते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में जहां करीब 45 हजार कर्मचारियों को एसीपी के मुद्दे पर खुशखबरी सुनाई है वहीं करीब 10 हजार कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया गया है। सरकार ने इस साल भी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की है, पर इस बार यह केवल यूपी बोर्ड के मेधावियों को ही दिए जाएंगे। लैपटॉप बांटना मुख्यमंत्री की आधुनिक सोच को दर्शाता है, पर इसका लाभ तबतक नहीं मिलेगा जबतक प्रदेश की आबादी में शिक्षा का स्तर ना बढ़े। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले साल बंटे लैपटॉपों को लेने वाले कई छात्रों ने कंम्प्यूटर फ्रैंडली ना होने के कारण इसे अपने संबंधियों को दे दिया या कम कीमत में बेच दिया था। प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग और कलाकारों की स्थिति के आधार पर करोड़ों का अनुदान देने का भी फैसला हुआ। टेक्सटाइल और टेंट आदि उद्योगों को प्रोत्साहन देने को भी टैक्स में राहत दी गई। हालांकि आम जन के हित में फैसले के मुकाबले जिस तरह से अखिलेश सरकार ने फिल्म आदि को लेकर कई उत्साहवर्धक फैसले किए हैं,उससे मामला फिल्मी सा होता लगता है। राज्य में फिल्मोद्योग के विकास के लिहाज से किए गए ये फैसले वाजिब हैं, पर शासन व्यवस्था, अपराध आदि के क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति को संभालने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

मुख्यमंत्री की प्रेस कांफ्रेंस में जिस तरह से ऐन वक्त पर बिजली गुल हो गई, वह प्रदेश में कार्यकारी व्यवस्था की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। जांच पर पता चला कि तारों के जंजाल के बीच कोई मरा चूहा फंसा पड़ा था। व्यवस्था के संजाल के बीच फंसकर मर जाने वाले चूहे, व्यवस्था को अपडेट करने की जरूरत को दर्शाते हैं। यह केवल लैपटॉप बांटने से नहीं होगा, इसके लिए मानसिक स्तर पर भी आम जन को अपडेट करना होगा। तभी मोदी के विकास के नारे का मुकाबला कर पाएगी प्रदेश की सपा सरकार।

**<u>महाराष्ट्र में सरकार 22-10-14</u>**

हाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बहुमत से दूर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा ने परदे के पीछे चल रहे खेलों पर नियंत्रण पाने का मौका निकाल लिया है। उसने चुनाव नतीजों के आने के तीन दिन बाद भी मुख्यमंत्री के चुनाव को दिवाली बाद के लिए टाल दिया है। मुख्यमंत्री की तलाश करने वाले पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा अपना मुंबई दौरा रद्द कर चुके हैं। पार्टी यह तय नहीं कर पा रही कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? नतीजों के बाद कई नाम महाराष्ट्र में उछाले जा रहे हैं, लेकिन अपनी उम्मीदवारी से लगातार इनकार कर रहे नितिन गडकरी का नाम वजनी होता दिख रहा है। महाराष्ट्र भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने भी गडकरी के नाम की वकालत की है। हालांकि चर्चा में देवेन्द्र फडणवीस का नाम ज्यादा उछल रहा है। मुनगंटीवार, गडकरी और फडणवीस तीनों महाराष्ट्र के विदर्भ से आते हैं।

शिवसेना के नखरों को देखते हुए फिलहाल भाजपा शिवसेना या किसी अन्य संभावित सहयोगी दल से बातचीत के मूड में नहीं है। वह सोच रही है कि वह पहले मुख्यमंत्री और कैबिनेट को शपथ दिला दे फिर सदन में बहुमत जुटाने को कदम उठाए। इस तरह से वह शिवसेना की उप मुख्यमंत्री पद या अन्य अहम मंत्रालय की आकांक्षा को पहले ही काटकर फिर उससे सर्मथन पाने की रणनीति पर चल रही है। भाजपा में महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी राजीव प्रताप रूड़ी का कहना है कि अगर शिवसेना हमें सर्मथन दे या सरकार में शामिल हो, तो हमें खुशी होगी, लेकिन उन्हें अपना रुख नरम करना होगा। वे शर्तें नहीं रख सकते हैं। रूड़ी कहते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मशविरा कर पार्टी की स्टेट लीडरशिप ने यह बात तय कर ली है। भाजपा यह मानकर चल रही है कि वह निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर और शरद पवार की एनसीपी के बाहर से सर्मथन के दम पर सदन में 145 विधायकों का सहयोग जुटा लेगी। शिवसेना के साथ भाजपा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी (एमएनएस) को भी पाठ पढ़ाने के मूड में है। एमएनएस के इकलौते विधायक शरद सोनवने अगर भाजपा में शामिल होने का न्योता स्वीकार लेते हैं तो एमएनएस महाराष्ट्र विधानसभा में खाली हाथ रह जाएगी। शरद के पाला बदलने से रोकने को एमएनएस की कसरत जारी है, क्योंकि शरद अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी के अकेले विधायक होने के कारण उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। देखा जाए तो चुनावों में गठबंधन टूटने पर प्रधानमंत्री मोदी को अफजल जैसा धोखेबाज बताने वाली शिवसेना और आलोचना में उसका साथ दे रहे एमएनएस को भाजपा पाठ पढ़ाने के मूड में दिख रही है। वहीं शिवसेना ने घोषित किया कि वह किसी के पास नहीं जाएगी, जिसे सर्मथन चाहिए वह उसके पास आए। अब भाजपा ने इसका जवाब देते हुए तय किया है कि बातचीत की पहल अगर करनी है तो शिवसेना करेगी, भाजपा नहीं।

**<u>मुशर्रफ के विवादी बोल 18-10-14</u>**

ष्ट्रद्रोह और हत्या की साजिश का मुकदमा झेल रहे मुशर्रफ के भीतर अचानक उमड़े राष्ट्रप्रेम की मजबूरी को समझा जा सकता है। पाकिस्तान सरकार द्वारा लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में मसले को भारत के साथ ही सुलझाने की सलाह दी है। इस सलाह से पैदा शर्म को आक्रोश में बदलने की नीयत और पाकिस्तान की जनता को उन्मादी बनाने की फितरत से दिया मुशर्रफ का बयान उन्हें ही हास्यास्पद बनाता है। मुशर्रफ ने यह भी कहा है कि सीमा पर पाकिस्तान की जवाब देने की एक सीमा है, क्योंकि आखिरकार उसकी गोलियों का शिकार कोई कश्मीरी ही बनता है। मजेदार बात यह है कि बिना किसी प्रसंग के मुशर्रफ ने ना केवल कश्मीर का मुद्दा उठाया बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को मुस्लिम और पाकिस्तान विरोधी बताकर दोनों देशों के बीच बनने वाले संभावित सौहार्दपूर्ण संबंधों में भी टांग अड़ा दी है।दीगर है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में भारत बुलाकर अपनी ओर से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने सीमा पर लगातार आक्रामक रुख अपनाया तो उनका जमकर जवाब देने के लिए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटे।

कश्मीर हमारे देश से जुड़ा अहम मसला है। इसके बावजूद नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के बीच कारगिल युद्ध के सूत्रधार मुशर्रफ ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की नसीहत दी है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अलावा लाखों लड़ाकों की बात करते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत को आसानी से दबोच लेने की भी बात की। मुशर्रफ भूल गए कि कारगिल युद्ध के समय वे खुद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे और उस समय भारतीय जवानों ने अपनी ताकत के बल पर पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने अतिश्योक्तिपूर्ण बयानों में मुशर्रफ ने खुद के परमाणु शक्ति संपन्न होने की धमकी भी दी, जैसे भारत हर तरह से उनका बड़ा भाई ना होकर कोई छुईमुई गुड़िया हो। देखा जाए तो 1998 में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर तरजीह देते हुए परवेज मुशर्रफ को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ही सैन्य प्रमुख बनाया था। वही मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ का ही तख्तापलट कर देश के प्रमुख बने। और अब अपने उल्टे-सीधे कथनों से वे शरीफ की राह को लगातार कठिन बना रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि जब तक मुशर्रफ पर पाकिस्तान की अदालत की तलवार लटकती रहेगी, तब तक वे इसी तरह गाहेबगाहे कश्मीर के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हुए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहेंगे। अदालत ने तो उनके विदेश जाने तक पर रोक लगा रखी है, ऐसे में बेचारे मुशर्रफ अपनी कल्पना की सेना के साथ कश्मीर प्रवेश का दु:स्वप्न देखते रह सकते हैं।

**संकल्प का सुसाइड 17-10-14**

द्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज में नौकरशाहों को मुश्तैदी से अपने काम काज निपटाने पड़ रहे हैं और खबर है कि समय सीमा में काम पूरा करने के लिए अधिकारी शनिवार को भी काम पर लगे रहते हैं। पर मोदी की इस सख्ती का क्या भ्रष्ट हो चुकी इस व्यवस्था की आंतरिक बनावट पर भी कोई असर पड़ रहा है या पड़ेगा ? यह तो वक्त ही बताएगा। दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित 'क्रांति','रोटी, कपड़ा और मकान', 'प्यासा सावन', 'जुनून', 'शोर', 'प्रेमरोग' और 'सूर्या' समेत तमाम फिल्मों में गाने लिखने वाले मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे, संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी ने बुधवार को मथुरा के कोसीकलां में इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। संकल्प आनंद लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में समाज विज्ञान के लेरर थे। उनका सुसाइड नोट नौकरशाही में पैठे भ्रष्टाचार के पोषक अपराधी प्रवृत्ति के तानाशाहों की उपस्थिति को प्रमाणित कर रहा है। खुदकुशी का यह मामला उलझता जा रहा है। दस पेज के सुसाइड नोट में संकल्प ने करोड़ों की हेराफेरी में फंसाए जाने का जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय में नियुक्त डीआइजी संदीप मित्तल और इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक कमलेंद्र प्रसाद समेत एक दर्जनों लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

सुसाइड नोट से उभर रहे तथ्यों के प्रकाश में यह आसानी से समझा जा सकता है कि संकल्प एक भारी मानसिक तनाव में चल रहे थे। संकल्प के खाते को आधार बनाकर फर्जी जॉब रैकेट चलाकर उच्चाधिकारी मोटा पैसा बना रहे थे। दिसंबर, 2012 में रोजगार समाचार-पत्र के भर्ती विज्ञापन से देश भर से दलालों ने करोड़ों रुपये इकट्ठे किए थे। मामले की सघन जांच हो तो इसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी भी फंस सकते हैं, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट किसी लेरर को आगे कर दो साल से उसके खाते में करोड़ों की रकम मंगा रहा था। बाद में जब लोगों ने संकल्प से पैसे वापस मांगना शुरू किये तो संकल्प दबाव में आते गए। लोग पैसे वापस ना मिलने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगे। इस संबंध में जब उन्होंने संबद्ध अधिकारियों से बात की तो उन्होंने टके सा जवाब दिया कि यह तुम्हारी समस्या है। इस तरह लगातार मानसिक रूप से घिरते गए सकंल्प को अंततः आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। अपनी नौकरी पक्की कराने के चक्कर में संकल्प भ्रष्ट अधिकारियों के दुष्चक्र में फंसते चले गए थे। यह सब जिस तरह केंद्र सरकार और रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया की नाक के नीचे हो रहा था, उससे लगता है कि करोड़ों के इस लेन-देन को उच्च संरक्षण प्राप्त था। एक संकल्प ने अपना जीवन जीने का संकल्प तोड़ा तो दर्जनों लोगों के संदिग्ध चेहरे सामने आए। पता नहीं और कितनों के संकल्प इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में टूट रहे हों, क्या इस सब पर काबू पाया जा सकेगा। या अच्छे दिनों की सरकारें इसी तरह आती जाती रहेंगी।

**भारत-पाक सीमा विवाद 16-10-14**

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन के समय भारतीय सीमा क्षेत्र में आने वाले चुमार में चीनी सैनिकों की उपस्थिति ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी कराई थी। उसके बाद पाकिस्तानी सीमा पर पाक सैनिकों ने भी लगे हाथ भारतीय सीमा पर घुसपैठ और फायरिंग कर भारतीय धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की। पाक का ऐसा बड़ा हमला पिछली मनमोहन सिंह की सरकार के समय कभी नहीं हुआ था। उससे पहले वाजपेयी की सरकार के समय भी पाक ने ऐसी ही हरकत की थी, पर इसका भारतीय सेना ने जमकर जवाब दिया। इस तरह बगलें झांकने को मजबूर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाकर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहा, पर इस बार भी उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग करने वाले पाकिस्तान को इस वैश्विक संस्था ने कोई नया जवाब ना देकर यह दोहरा दिया कि इस विवाद का दीर्घकालिक हल निकालने के लिए भारत और पाकिस्तान को वार्ता के जरिये अपने मतभेद सुलझाने चाहिए।

देखा जाए तो पाक को एक महीने में तीसरी बार यूएनओ ने कश्मीर मुद्दे पर खरी-खरी सुनाई है। सितंबर के अंत में पाक पीएम नवाज शरीफ ने यूएनओ महासचिव बान की मून से भेंट कर व फिर मंच से अपने संबोधन में इस मुद्दे को उठाया था। इस पर मून ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया था। फिर जम्मू-कश्मीर में गोलीबारी के बाद मून के प्रवक्ता ने पाक को कश्मीर मुद्दे पर भारत से बात करने को कहा था। और, अब तीसरी बार पाकिस्तान द्वारा पत्र लिखे जाने पर यूएनओ ने उसे भारत से बात कर कश्मीर विवाद सुलझाने को कहा है। दोनों देशों के बीच के इस विवादित क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ने लंबे समय से अपनी संस्थागत मौजूदगी बनाए रखी है। यूएन मिलिट्री ऑब्जवर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान (यूएनएमओजीआइपी) नियंत्रण रेखा पर एवं जम्मू-कश्मीर में दक्षिणी एशियाई पड़ोसियों के बीच की कार्यकारी सीमा पर होने वाले संघर्ष विराम उल्लंघनों पर नजर रखता है और इनकी रिपोर्ट तैयार करता है। इसके साथ ही यह उन परिवर्तनों की भी जानकारी देता है, जिनका नतीजा संघर्ष विराम के उल्लंघन के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, भारत हमेशा से यूएनएमओजीआइपी को अप्रासंगिक बताते हुए इस मुद्दे पर उसकी किसी भूमिका से इनकार करता रहा है।

अब पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी के चलते आठ लोग मारे गए हैं।कई घायल हुए हैं तो हजारों बेघर होकर भटकने को मजबूर हैं।संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत हमेशा से सकारात्मक माहौल बनाने की मांग करता रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र के लगातार जवाब और भारतीय सेना के कड़े जवाबी रुख के बाद पाकिस्तान को इस मुद्दे पर विचार करना होगा। अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से उसका साथ देते रहने वाले अमेरिका और चीन भी भारत के प्रति पुराना रवैया बदल रहे हैं। व्यवसाय केंद्रित होती जाती दुनिया में अब युद्ध पहले की तरह किसी देश के आधारभूत तत्वों के निर्धारण का आधार नहीं रह गए हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देने की बात कही है। पाक को भी उससे सीख लेनी चाहिए। वैसे भी भारत आकार या प्रकार में किसी भी तरह ऐसी हालत में न तो था और ना है कि वह उसे घुड़की देकर अपना कुछ भला करा सकेगा या उस पर दबाव बना सकेगा।

**किसान स्वाभिमान रैली 14-10-14**

जीत सिंह से 12 तुगलक रोड स्थित उनका सरकारी आवास खाली कराया जाना केंद्र सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अजीत सिंह के आवास को पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता उनके पिता चौधरी चरण सिंह के स्मारक के रूप में तब्दील कर देना चाहते हैं, क्योंकि अजीत सिंह से पहले लंबे समय तक वह आवास चौधरी चरण सिंह का आवास था। चौधरी चरण सिंह के स्मारक के बहाने मेरठ के गायत्री मैदान में आयोजित किसान स्वाभिमान रैली ने न केवल पिछले लोकसभा चुनावों में बागपत जैसा अपना अभेद्य दुर्ग खो चुके रालोद को नवजीवन प्रदान किया बल्कि इसी बहाने लोकसभा चुनावों में बिखर चुके तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की भी तलाश सबने मिलकर की। रैली में उमड़ी भारी भीड़ और महागठबंधन की सुगबुगाहट ने सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं के मन में उम्मीदों की नई किरण जगाई है। रैली में बंगले की राजनीति को रंग देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि हारकर भी बिहार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बंगलों में रह रहे हैं, अजीत सिंह से कोठी खाली कराने वालों को जनता जरूर याद रखेगी।

अजीत सिंह के आह्वान पर विगत रविवार को मेरठ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद केसी त्यागी, रालोद नेता जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव सहित कांग्रेस, सपा और जनतादल (यूनाइटेड) के नेतागण और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा एक साथ मंच साझा करते दिखे। इस रैली ने उत्तर प्रदेश और देश के किसानों के मन में चाहे आशा की नई किरणें जगाई हों पर देखना होगा कि बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की इस बहाने की गई पहल आगे कहां तक इन्हें साथ ले जाती है और इस जनमत को वे लोकतंत्र और अपने सपनों के समाजवाद के हित में कहां तक मोड़ पाते हैं? क्या इसके पीछे सचमुच चरण सिंह के विरासत की चिंता है या फिर यह अपना राजपाट खो चुके नेताओं की अपनी साख वापसी की एक कोशिश मात्र है। रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बिहार की तरह देश भर में एकता की जरूरत है। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफाई अभियान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जनता की जगह झाड़ू के अच्छे दिन आ गये।

इधर रैली में शरद यादव भी कम नहीं पड़े। शरद यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा ने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और किसान एकता को कमजोर

करने के लिए साजिश के तहत जाटों और मुसलमानों को अलग-अलग किया है। हम उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। शरद यादव ने कहा किसान खंड-खंड हैं, इसीलिए देश में सियासी पाखंड है। वहीं रैली में चौधरी चरण सिंह को भारत र} देने का प्रस्ताव भी दिया गया। कुल मिलाकर रालोद ने इस रैली में आक्रामक समाजवादी-लोहियावादी राजनीति के सहारे एक बार फिर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाने की पुरजोर कोशिश की है कि रैली से उठे मुद्दे थर्ड नहीं फस्र्ट फ्रंट बनाएंगे, बस आपसी मतभेदों को भुलाना होगा। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन यह सियासत है, इसकी चौपड़ पर जनता को किस 'चाल' से चला दिया जाए, कहा नहीं जा सकता।

**हुदहुद के बाद 13-10-14**

गाल की खाड़ी में करीब तीस किलोमीटर विस्तार वाला चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापत्तनम के तट से टकरा कर आगे बढ़ चुका है और इसकी चपेट में आकर कुछ लोगों के मरने की खबरें आंध्र के शीकाकुलम और उड़ीसा से आ रही हैं। 170 से 180 किमी. प्रति घंटा की हवाओं की रफ्तार वाले इस तूफान से लोहा लेने की तैयारियां केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले से कर रखी थीं। तूफान आने से पहले आंध्र प्रदेश के पांच जिलों से डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि ओडिशा में करीब चार लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बीते साल इसी समय फैलिन तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था, जिसका भारतीयों ने जमकर और सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। इससे बड़ी संख्या में लोगों को खतरे की जद में आए इलाकों से निकाल कर जानमाल की बड़ी हानि को टाला जा सका। इस बार भी हम मुस्तैद थे, हालांकि हुदहुद की तीव्रता फैलिन जितनी नहीं है। आंध्र और ओडिशा के अलावा हुदहुद का असर झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में भी देखा गया और वहां खासी बारिश हुई है। रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, प. सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो व धनबाद में इसे लेकर पहले से हाइअलर्ट जारी था। इससे पहले ऐसे तूफानों के नाम नर्गिस, लैला, कैटरीना, नीलम, फैलिन आदि रखे जाते थे, जो सामान्यत: महिलाओं के नाम रहे हैं। साइक्लोन, हरिकेन या चक्रवात के नामकरण की शुरुआत यह सोच कर की गईथी कि इससे होने पाले खतरे का संदेश आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। लोगों का मानना है कि चक्रवात के आसान नाम से इसे याद रखने में आसानी होती है। एक तरह से कठिन स्थितियों के लोगों पर बनने वाले मानसिक दबाव को ऐसे नामों से कम करने की कोशिश की जाती रही है। पहले मनमाने ढंग से इन तूफानों का नामकरण कर दिया जाता था, पर 1990 के दशक की शुरुआत से साइक्लोन का नामकरण ज्यादातर महिलाओं के नाम से किया जाने लगा।

समुद्री तूफानों की भयावहता अपने वक्त को दहला देने वाली होती है, पर इंसान के जीवट का भी जवाब नहीं होता। विषम से विषम परिस्थितियों में भी वह धीरज नहीं खोता और संकटों का सामना करता रहता है। इस बार भी संकट कम नहीं था। पर, साल भर पहले के इससे बड़े तूफान फैलिन से निपटने का अनुभव और आत्मविश्वास हमारे साथ था। मीडिया की भी इस दौरान लोगों को जागरूक करने वाली सजगता सराहना के काबिल दिखती है। हालांकि, इसकी अति कई बार हमारे संकटों का तमाशा भी बना देती हैं, पर कुल मिलाकर मीडिया अपनी जीवंत भूमिका निभाता आया है। ऐसे तूफानों के बाद आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की देखभाल और उनको फिर से जीवन की मुख्यधारा में लाने की चुनौती हमेशा कठिन रहती है और आगे इसकी चपेट में आए लोगों को उनके रोजमर्रा के दुखों से निजात दिलाने की कोशिशों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

**अधिवेशन के निहितार्थ 11-10-14**

खनऊ के जनेश्वर मिर्श पार्क में चल रहा समाजवादी पार्टी का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन स्थानीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। इस दौरान केंद्र पर हमले की रणनीति अपनाते हुए मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की जनता और सपा सर्मथकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर है। इस दौरान पार्टी के 22 वर्ष के संघर्ष का जिक्र कर उन्होंने जनता से कहा कि पार्टी आज जिस मुकाम पर है, वहां वह एक लंबे संघर्ष के बाद पहुंची है। भारत-पाक तनातनी के माहौल के तीखेपन को भी सपा ने सत्ताधारी भाजपा की ओर करने की यथासंभव कोशिश की। मुलायम ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हिन्दुस्तान का सामना नहीं कर पाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस गोलीबारी के बहाने देश की कुछ शक्तियां सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रच रही हैं। अखिलेश यादव के हमले का केंद्र भी मोदी सरकार ही रही। केंद्र की गलत नीतियों के कारण जीवन रक्षक दवाइयों के महंगे होने को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने कहा कि आज गम्भीर रोगों का इलाज कराना गरीबों के बूते के बाहर हो गया है। केंद्र के स्वच्छता व गंगा सफाई अभियान पर भी सपा हमलावर दिखी। अखिलेश ने गंगा के साथ देश की सभी नदियों की सफाई की बात करते हुए कहा कि नदियों की सफाई के बहाने केंद्र सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है जबकि नदियां धर्मनिरपेक्ष होती हैं। वे किसी एक वर्ग के काम नहीं आती हैं। समापन भाषण में सपा अध्यक्ष का मुख्य जोर आंतरिक भाईचारे और सामाजिक एकता पर रहा। एक अरसे से उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहे सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल का दबाव अधिवेशन में देखा गया। सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां ने मुस्लिम समुदाय को ईद की बधाई नहीं देने को लेकर मोदी को घेरे में लिया। क्योंकि पिछले महीने मोदी ने मुसलमानों को देशभक्त संबोधित किया पर ईद जैसे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर मुस्लिमों को बिसारना बतलाता है कि मुसलमानों को लेकर उनका नजरिया राजनीतिक और वोटो के गणित को ध्यान में रखने वाला है ना कि राष्ट्रीय नेता का।

अधिवेशन में पार्टी की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की भी कोशिशें हुईं। यहां ध्यान देना होगा कि आगे बढ़ाए जा रहे अधिकांश युवा नेता मुलायम सिंह के परिवार से आते हैं। सपा अगर पूंजीवाद और समाजवाद की पुरानी बहस को सामने लाने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने इस परिवारवाद से भी जूझना होगा। यह उनके लिए मुख्य चुनौती भी है,क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की आलोचना बराबर कर रहे हैं और इसका कोई जवाब सपा और कांग्रेस के पास नहीं है। अगर सपा अपने परिवार से बाहर जाकर आम युवा को संगठित करने की कोशिश कर पाती है तो यह उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि मोदी ने युवा वर्ग को ही अपने ध्यान में रखा है और इसका लाभ उन्हें मिला है।

**सपा का अधिवेशन 9-10-14**

खनऊ में चल रहा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन क्या बिखराव के कगार पर पहुंच चुके समाजवादी सपनों को फिर से नई जमीन मुहैया कराने की दिशा में किसी कारगर पहल को सामने ला सकेगा या वह अखिलेश सरकार को ज्यों का त्यों बनाए रखने की कोशिशों तक खुद को सीमित रखेगा? जनेश्वर मिर्श पार्क में चल रहे सपा के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव लगातार नौवीं बार सर्वसम्मति से अगले तीन सालों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। मुलायम का अध्यक्ष चुना जाना तयशुदा था, पर जिस बात ने राष्ट्रीय राजनीति के विषकों को चौंकाया है, वह है मंच पर जनता दल (यू)के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का उपस्थित होना। सम्मेलन में अन्य पुराने समाजवादी भी पहुंचे थे जिन्हें देखकर मुलायम का खुश होना वाजिब था। इस जुटान ने उन दिनों की याद भले ही ताजा कर दी हो, जब सपा ने महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। पर, इस खुशी के कोई सकारात्मक निहितार्थ तभी निकल सकेंगे, जब सपा खुद के सत्तावादी चेहरे से अलग समाज में बिखराव को बढ़ावा देने वाली शक्तियों को रोकने और जनमत को पहले की तरह प्रभावित करने की दिशा में खुद को खड़ी कर सके। विगत लंबे समय से सपा उत्तर प्रदेश में सामाजिक ताने-बाने के बिखराव को रोक पाने में असफल दिख रही है और प्रदेश दंगों से लेकर तथाकथित लव जिहाद तक की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है।

शरद यादव और मुलायम हमेशा से अच्छे मित्र रहे हैं। पर, इस बीच आई दूरी को पाट उनका इस तरह साथ दिखना समाजवाद के बिखरते सपनों को फिर से रूपकार देने की नयी कोशिशों की तरह देखा जा सकता है। शरद यादव ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में समाजवादियों ने एकजुटता दिखाई है। हम लोग एक-दूसरे की मदद के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सपा के साथ किसी तरह के गठबंधन के बारे में जद(यू) अध्यक्ष ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर, मुश्किल घड़ी में एकजुटता की उनकी पहल नया रंग तो दिखा ही सकती है। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठजोड़ ने जिस तरह से लव जिहादियों की बाग थामी है। ऐसे में शरद की यह उपस्थिति अपने सत्ताजाल में उलझती जा रही सपा के लिए संजीवनी बन सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी शरद और मुलायम ने ऐसी कोशिश की थी कि भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे को खड़ा किया जाए, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। गाहे-बगाहे जनता परिवार को साथ लाने की कोशिश हमेशा की जाती है। बिहार में जब नीतीश और लालू ने साथ आने का निश्चय किया, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि सभी समाजवादी शक्तियों को साथ आ जाना चाहिए और यूपी में मुलायम और मायावती को भी मतभेद भुलाकर मित्रता करनी चाहिए।

**हिन्दुत्ववादी राजनीति 7-10-14**

कारात्मक सोच वाले मानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। कल तक गलबहियां देकर साथ चलने वाले कब साथ चलने वाले की पीठ में चाकू उतार देने की मुद्रा में आ जाएं, नहीं कहा जा सकता। और अब जब शिवसेना यह कह रही है कि गठबंधन तोड़कर भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है तो मित्र-शत्रु वाली कहावत के निहितार्थ स्पष्ट होते हैं। महाराष्ट्र चुनावों के एन पहले राज्य में ज्यादा सीटों के मसले पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ढाई दशकों से चला आ रहा राजनीतिक गठबंधन और साथ टूटा, वह लोकसभा चुनावों के बाद हुए उपचुनावों में लगातार हार और फजीहत का सामना कर रही भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है कि उसका शिवसेना से टकराव बढ़े नहीं, पर राज्याकांक्षा है कि वह दोनों के हिन्दुत्ववादी आवरण को चीर-फाड़ कर उनका असली रूप सामने ला दे रही है। बचाव में मोदी कहते फिर रहे हैं कि वे शिवसेना पर नहीं बोलकर बालासाहब का सम्मान कर रहे हैं, पर शिवसेना यह कैसे भूल जाए कि राज्य में मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, यह मानना भाजपा ने स्वीकार नहीं किया। अब भाजपा अगर राज्य में बहुमत की मांग करते हुए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है तो इसे शिवसेना कैसे स्वीकार कर सकती है? आखिर उसके पास शेष भारत का अखंड राज्य तो है नहीं। वह भाजपा से ऐसी आशा तो कर ही सकती थी कि वह महाराष्ट्र उसके लिए छोड़े। पर, अब जबकि शिवसेना को अधर में छोड़ भाजपा ने एकला चलो की राह पकड़ ली है, तब जाकर सेना को होश आया है कि भाजपा के लिए सत्ता और बाजार सब कुछ है और वह कांग्रेस से अलग नहीं है। सेना ने गुजरात की मुख्यमंत्री की महाराष्ट्र यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आनन्दी बेन पटेल किस उद्देश्य से महाराष्ट्र आई थीं? अगर वह सभी उद्योगपतियों से महाराष्ट्र छोड़ कर गुजरात में अपना आधार बनाने के लिए कहती हैं तो यह भी महाराष्ट्र को लूटना ही हुआ।

शिवसेना ने मोदी के बालासाहब का सम्मान करने को एक बाजारू शोशा करार देते कहा है कि पहले कभी किसी ने शिवाजी महाराज के आशीर्वाद का बाजार नहीं बनाया। भाजपा और शिवसेना की इस कटुता के बाद अब यह भी माना जा रहा है कि अपने-अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एकसाथ आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भाजपा विरोधी एजेंडा दोनों के बीच दूरियां खत्म कर सकता है और वे साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे का कहना है कि शिवसेना को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भाजपा भरोसे लायक नहीं। भाजपा-शिवसेना के अलगाव को हम देखें तो हिन्दुत्ववादी राजनीति की सीमाओं और अंतरविरोध को हम समझ सकते हैं। क्षेत्रीयतावाद और जात-पांत जैसे आग्रह जिस तरह हिन्दुत्ववाद के साये में पलते हैं, वे कभी भी अपनी छाया में चलने वालों को दूर तक एक होकर चलने नहीं दे सकते।